शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार मीमांसा
मध्यप्रदेश

भास्कर

आर्थिक संकट • चिंता में शिक्षा विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी

सरकारी शिक्षक बनने के लिए छोड़ा प्राइवेट स्कूल, परीक्षा पास की, ज्वॉइनिंग नहीं मिली, अब बच्चों की फीस भरना तक मुश्किल

भास्कर संवाददाता | होशंगाबाद

शिक्षा विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग ने वर्ग- 1, वर्ग -2 और वर्ग 3 में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की। 2019 में रिजल्ट जारी हुआ। मैरिट के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन, काउंसलिंग और च्वाइज फिलिंग भी करवाई गई। शिक्षक के पद पर भर्ती होने की उम्मीद में निजी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों ने प्राइवेट जॉब छोड़ दी। काउंसलिंग, सत्यापन के लिए बार- बार छुट्टियां लेने में परेशानी हो रही थी ऐसे में शिक्षकों ने अवैतनिक अवकाश भी ले लिया। ज्वानिंग हुई नहीं और कोरोना के कारण स्कूल भी नहीं खुले। अब जॉब छोड़ चुके शिक्षकों को परिवार के खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फीस और लोन की किश्त भरना भी कठिन हो रहा है। हालांकि शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभी शिक्षा विभाग और आदिमजाति कल्याण विभाग ने कोई भी प्रक्रिया तय नहीं की है।

केस 1: मीना भदौरिया

दो साल हो गए जॉब भी गई ज्वाइनिंग भी नहीं हुई

होशंगाबाद निवासी मीना भदौरिया होशंगाबाद के निजी स्कूल में शिक्षक थीं। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास होने और काउंसलिंग का शेड्यूल आने पर बीच सत्र में स्कूल ना छोड़ना पड़े इसलिए जॉब छोड़ दी। दो साल होने को हैं प्राइवेट जॉब भी गई और नियुक्ति प्रक्रिया भी रुक गई। बच्चों की फीस भरना भी कठिन हो रहा है।

केस 2: चित्रा चौरे

हाथ का काम भी गया और कोरोना ने कमर तोड़ दी

बेगनिया निवासी चित्रा चौरे ने शिक्षक भर्ती का शेड्यूल आने के बाद काउंसलिंग, सत्यापन के लिए बार- बार छुट्टी ना लेना पड़े इसलिए स्कूल छोड़ दिया। अब होम लोन के लिए किश्त चुकाना मुश्किल हो रहा है। उनके दो बच्चे भी हैं। परिवार में आर्थिक सहयोग करने के लिए निजी ट्यूशन भी लेती हैं।

जानकारी भेजी है

शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई निर्देश शिक्षा विभाग को नहीं दिए गए हैं। जब भी शिक्षा विभाग से निर्देश आएंगे रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाएगी और सत्यापन काउंसलिंग के शेड्यूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- आरके गुप्ता, एडीपीसी

देवास में शिक्षा विभाग का समन्वयक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई

देवास, (एजेंसी)। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने देवास में एक वरिष्ठ शिक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शिक्षक ने बच्चों के मध्याह्न भोजन वितरण का ठेका देने के लिए रिश्वत मांगी थी। माध्यमिक शाला में महिला स्वसहायता समूह करता है मध्याह्न भोजन का वितरण करता है। यहां मध्याह्न भोजन के ठेके को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक रिश्वत ले रहा था। आरोपी वरिष्ठ शिक्षक होकर भी विकास खंड स्त्रोत समन्वयक शिक्षा विभाग के पद पर पर कार्यरत है।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने बुधवार को देवास में नेवरी फाटे पर शिक्षा विभाग के समन्वयक पद पर कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक जीवन सिंह को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी ने मध्यान भोजन के ठेके को आगे बढ़ाने के लिए 5000 की रिश्वत मांगी थी। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान को आवेदक शिवनारायण मालवीय निवासी नराना ने शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी का उमंग स्व सहायता समूह शासकीय माध्यमिक विद्यालय नराना में मध्याह्न भोजन बनाने का ठेका है, जिसे आगे बढ़ाने के लिये आरोपी जीवन सिंह विकास खंड स्त्रोत समन्वयक सोनकच्छ द्वारा 5000 की रिश्वत की मांग की है। फरियादी से जीवन सिंह ने 1000 हजार 22 फरवरी को लिए थे।

वहीं बाकी रुपए 4000 की रिश्वत लेने के लिए बुधवार को बुलाया था। जहां पर उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने उनकी टीम के साथ यहां पहुंचकर कार्रवाई पूरी की। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने शिक्षक पर धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी कह रहा है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। गाड़ी पर पत्नी में पैसे रख के उठाए गए हैं और मुझ पर झूठा प्रकरण डाला जा रहा है। पुलिस ने भी देखा है पुलिस भी यहां मौजूद थी।

प्रदेश में बेरोजगारी बरकरार है...

आइए! लगवाएं कोरोना पर जीत का टीका

नौकरी की आस में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, विभागों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी दामन नहीं छोड़ रही

35 लाख* बेरोजगार, 90 हजार पद खाली...न परीक्षा, न भर्ती, न नियुक्ति

*ये आंकड़ा सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है

राहुल शर्मा/भीम सिंह मीणा | भोपाल

प्रदेश में बेरोजगारी बरकरार है... सरकारी विभागों में नियुक्ति और भर्ती को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 90 हजार से अधिक पद खाली हैं। बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं, जहां चयन के बाद भी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे। नतीजा- उम्मीदवार नौकरी की आस में विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

हालात यह हैं कि पिछले तीन साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा भी नहीं हुई है। निजी एजेंसियों के मुताबिक प्रदेश में डेढ़ करोड़ बेरोजगार हैं। राज्य सरकार के रोजगार पोर्टल पर करीब 35 लाख से बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। इनमें 90 फीसदी मप्र के मूल निवासी हैं।

2018 तक ही चल पाया मप्र रोजगार बोर्ड

90 फीसदी बेरोजगार मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं

1.50 करोड़ बेरोजगार हैं प्रदेश में अनुमान के मुताबिक

03 साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा ही नहीं हुई

मेले तो लगते हैं,नहीं मिलता रोजगार: आईटीआई गोविंदपुरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में करीब तीन हजार आवेदकों ने भाग लिया गया। मेले में 20 से अधिक कंपनियों ने साक्षात्कार भी लिए।

ये है हालत... कुछ एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहे, कुछ काउंसलिंग

विभाग	पदनाम	रिक्त पद	कारण
स्कूल शिक्षा	शिक्षक	30,000	परीक्षा ली, काउंसलिंग नहीं की
पुलिस महकमा	आरक्षक	9000	आरक्षक का मामला आयु सीमा अटका,
स्वास्थ्य विभाग	एएनएम	9500	भर्ती पर विचार
राजस्व विभाग	पटवारी व अन्य	9530	भर्ती प्रक्रिया चल रही है
अजा-अजजा	तृतीय-चतुर्थ श्रेणी	4180	बजट की कमी
महिला बाल विकास	परियोजना समन्वयक	1000	एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहे है

कहीं उम्र आ गई आड़े तो कहीं इंटरव्यू तक हो गए, लेकिन पद खाली का खाली

स्कूल शिक्षा विभाग..

1 यहां सबसे ज्यादा 70 हजार पद खाली हैं

सबसे ज्यादा रिक्त पद स्कूल शिक्षा विभाग में हैं। यहां वर्ग एक और दो के तीस हजार रिक्त पदों के लिए तीन साल पहले परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे है और जिलों में आंदोलन भी कर चुके हैं। इसी तरह वर्ग तीन के फॉर्म भरवा लिए गए हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख ही घोषित नहीं की। तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा में ही 70 हजार पद खाली हैं। राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि कई स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं।

पुलिस..

2 तीन साल से भर्ती नहीं कई ओवरएज हो गए

पुलिस भर्ती में सबसे बड़ी समस्या आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है। इसे लेकर नाराजगी है। पहले इन पदों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष तय की गई थी, लेकिन तीन साल से भर्ती न होने की वजह से करीब तीन लाख उम्मीदवार ओवरएज हो गए। ये भी आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार सत्येंद्र द्विवेदी ने बताया कि आयु सीमा बढ़ाकर 37 वर्ष की जाए। इसके लिए आंदोलन भी किए गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस आरक्षक के 9 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा 6 मार्च से होना है।

कौशल विकास विभाग

3 यहां इंटरव्यू तक हो गए, नियुक्ति नहीं दी

2018 में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। उम्मीदवारों का चयन भी हो गया। 2019 में आवेदकों के इंटरव्यू, वेरिफिकेशन भी हो गया। लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। इसमें 102 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि कई बार विभाग में संपर्क किया गया, लेकिन यह कहा गया कि प्रक्रिया चल रही है। चयनित अभ्यर्थी नीरज वर्मा ने बताया कि इसमें मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों का चयन हुआ था। लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहा।

राजस्व विभाग

4 यहां वेटिंग वालों को नहीं मिला मौका

2017 में पटवारी के 9235 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इस परीक्षा में आठ लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल भी हुए। पीईबी ने मार्च 2018 में परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद वेटिंग में 1200 उम्मीदवार थे। जून 2018 में काउंसलिंग हुई और करीब 1300 पद रिक्त रह गए थे। लेकिन वेटिंग वालों को मौका नहीं दिया। विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने कहा कि एक हजार पद नहीं थे करीब 250 पद ही थे। अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई थी। इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है।

निजी कंपनियों में नहीं दिला पाए नौकरी.. 2016 में सरकार ने निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने मप्र रोजगार बोर्ड का गठन किया गया था। 2018 तक बोर्ड चला। तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत देशमुख ने ग्लोबल स्किल्ड समिट और रोजगार मेले लगाए। दावा किया कि 1 लाख लोगों को उत्पादन व सर्विस सेक्टर में नौकरी मिली है। हकीकत में इन्हें इंटर ऑफ लेटर दिए गए थे।

एक बार फिर भर्तियां करेंगे... सामान्य प्रशासन विभाग राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि दो साल पहले सरकारी विभागों में नियुक्तियां अटक गई और अब एक बार फिर से भर्तियां की जा रही हैं। कुछ परीक्षाओं को तकनीकी कारण से और कुछ में उम्मीदवारों की मांग देखते हुए देरी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर भर्ती हो और लोगों को रोजगार मिल जाए।

प्रायमरी, मिडिल स्कूलों के 1 लाख 97 हजार बच्चों को खाद्यान्न का इंतजार

बच्चों को दाल तो दे दी, तीन माह से रोटी-चावल देना भूले

पीपुल्स संवाददाता • शिवपुरी
editor@peoplessamachar.co.in

सरकारी योजनाओं के जिम्मेदार जो कुछ कर दें वह कम है। प्रायमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों के लिए चलाई जा रही मध्यान्ह भोजन योजना में अजब-गजब प्रक्रिया सामने आई है। कोरोना काल के चलते बच्चों को पिछले दिनों दाल और तेल के गिफ्ट हैम्पर का वितरण तो कर दिया, लेकिन विभाग यह भूल गया कि इस दाल को बच्चे खाएंगे कैसे? क्योंकि पिछले साल दिसंबर से बच्चों को न तो चावल दिया गया, न ही रोटी के लिए गेहूं। इस अजीब स्थिति पर जिम्मेदारों के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। बता दें कि जिले में प्रायमरी व मिडिल स्कूलों में 1 लाख 97 हजार बच्चे मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े हैं।

बच्चे पूछ रहे काहे से खाएं दाल...: नवंबर में तेल और दाल के गिफ्ट हैम्पर मिलने के बाद बच्चे और उनके परिजन खुश थे, लेकिन जब दिसंबर से गेहूं, चावल का वितरण नहीं हुआ और स्व-सहायता समूहों व स्कूलों के शिक्षकों ने ग्रामीणों को बताया कि फिलहाल खाद्यान्न के कूपन नहीं मिले हैं तो बच्चे व ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि इस दाल को काहे से खाएं...?

पीपुल्स समाचार
सरोकार

पहले दिया जा रहा था खाद्यान्न और पैसा

पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के बाद स्कूलों में पके हुए भोजन का वितरण बंद कर इसके बजाय बच्चों को समूहों के माध्यम से प्रतिदिन के आधार पर गेहूं व चावल वितरण किया जा रहा था, जबकि दाल, सब्जी व तेल मसाले के लिए निर्धारित राशि उनके खातों में भेजी जा रही थी। बाद में भोजन पकाने की राशि खातों में न पहुंचने की शिकायतों के चलते पिछले साल नवंबर में बच्चों को अगस्त, सितंबर व अक्टूबर की राशि की बजाय तेल और दाल के पैकेट वितरित किए गए, इसमें प्रायमरी के बच्चों को दो किलो दाल, आधा किलो तेल व मीडिल के बच्चों को तीन किलो दाल व 783 ग्राम तेल के पैकेट दिए गए।

कहां कितने बच्चों को मिलना है खाद्यान

ब्लॉक	छात्र संख्या
बदरवास	20605
शिवपुरी	26989
पोहरी	27465
खनियाधाना	36109
करैरा	20419
नरवर	20879
कोलारस	20439
पिछोर	24285

इनका कहना है

दिसंबर महीने से खाद्यान्न का आवंटन भोपाल से ही नहीं आया है। इस संबंध में कोई आदेश भी अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए इस संबंध में स्थानीय स्तर से और अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

सीमा उपाध्याय,
एमडीएम प्रभारी

दो सीटों के लिए 471 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

नौगांव। जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को 9वीं कक्षा की दो सीटों के लिये परीक्षा हुई जिसके लिये 741 छात्रों के द्वारा आवेदन किये थे। परीक्षा में 471 परीक्षार्थी उपस्थित हुये जबकि 270 अनुपस्थित रहे। प्राचार्य आरके सेजवार ने बताया कि 9वीं कक्षा में दाखिल छात्रों की संख्या के बाद दो सीटों रिक्त रह गई थीं जिन्हें भरने के लिये यह परीक्षा आयोजित करायी गयी। अब रजिल्ट आने पर जो भी छात्र मैरिट सूची में आएंगे उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ज्ञात हो कि 10 अप्रैल को 6वीं कक्षा के लिये परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 80 सीटों के लिये 11,295 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

राजएक्सप्रेस

एजेंसी देना है।

दैनिक राजएक्सप्रेस समाचार पत्र को बड़ामलहरा, हरपालपुर, सरवई, खजुराहो, गौरिहार और बारीगढ़ में रिपोर्टर नियुक्त कर एजेंसी देना है।

संपर्क करें- राजकुमार सेन (गोल्डू)

मो. नं. - +91 98268 01678

बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती कर देशभर में छात्रों को राहत दी है। इस विषय की परीक्षा 27 मई को निर्धारित है। बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में पांच अध्याय हटा दिए हैं। संशोधित पाठ्यक्रम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण इस सत्र में स्कूल काफी कम दिन चले हैं। अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऐसी स्थिति में छात्र, अभिभावक और शिक्षक पाठ्यक्रम कम किए जाने के पक्ष में हैं।

डीएलएड के छात्राध्यापक इंटर्नशिप से वंचित

» नही खुले प्राथमिक और माध्यमिक शालाओ के ताले

सतना। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते अभी भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद है। हमार घर हमारा विद्यालय के तहत कक्षाएं चल रही है लेकिन विद्यालय न खुलने के चलते जिले के एकमात्र सरकारी संस्थान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित 22 निजी शिक्षा महाविद्यालयों के हजारों हजार विद्यार्थी इस वर्ष इंटर्नशिप से वंचित रह गए। नवम्बर माह से इंटर्नशिप करवाई जाती है। इंटर्नशिप न होने का कारण कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के विद्यालयों का न खुलना है। बड़ी बात तो यह है विभाग में तीन बड़े जिम्मेदार हैं इनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को न खोलने के आदेश दिए थे। इन्ही आदेशों के परिपालन में विद्यालयों में ताला लगा हुआ है। यह ताला केवल विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षकों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। जबकि कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यालय ऑफ और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस साल का इंटर्नशिप नहीं होगा? या फिर विभाग इस पर भी छूट देगा।

इंटर्नशिप अनिवार्य

बताया जाता है कि डीएलएड के छात्राध्यापकों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य होता है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करना होता है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी कक्षा एक से पांचवी तक के और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी कक्षा छठवीं से आठवी तक के विद्यालयों में जाकर अध्यापन का कार्य करते हैं। इसके लिए उन्हे करीब 200 अंक मिलते हैं। यह एक तरह का प्रैक्टिकल वर्क है। जानकार बताते हैं कि निजी शिक्षा महाविद्यालयों में दाखिला से लेकर अंकसूची देने तक फर्जीवाड़ा की शिकायतें हैं। इंटर्नशिप भी इसी दायरे में आता है। हालांकि इंटर्नशिप न होने से निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सरकारी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के सामने संकट बना हुआ है।

धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाली स्कूल प्राचार्य की नहीं हुई गिरफ्तारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ खजुराहो

सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल की प्राचार्य भाग्या सिस्टर पर मामला तो दर्ज कर लिया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खजुराहो थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि शिक्षिका रूबी सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर अपराध क्रमांक 36/21 धारा 3/5 मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत कार्रवाई की गई है। शिक्षिका ने आरोप लगाया था कि प्राचार्य भाग्या ने उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का नाजायज फायदा उठाते हुए हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया। ईसाई धर्म न अपनाने पर स्कूल से अलग करने की भी धमकी दी गई। जबकि वह स्कूल में 2016 से शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही है। पहले उसे कम वेतन दिया जाता रहा लेकिन बाद में उसकी वेतन कुछ बढ़ा दी गई लेकिन इसी बीच उसके पति की मानसिक स्थिति खराब होने पर प्राचार्य ने दबाव बनाया कि वह हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना ले तो वेतन दोगुनी कर दी जाएगी और उसके बच्चों की शिक्षा उच्च स्कूलों में कराई जाएगी एवं पति का इलाज भी अच्छे अस्पताल में कराया जाएगा। इस दबाव से दुखी रूबी सिंह ने हिन्दू संगठनों से बात की। हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तब कहीं खजुराहो थाने में प्राचार्य भाग्या के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन

नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा केंद्रों में कराया जा रहा बदलाव

आष्टा में परीक्षा केंद्रों की सूची नजदीक के शासकीय विद्यालय से दूर के विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उसे मंजूर नहीं किया जाए। यदि ऐसा होता है तो इससे परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ आष्टा

आष्टा। प्रायवेट एसोसिएशन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन।

शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मनमानी के लिए प्रसिद्ध हो चुका आष्टा क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ चुनिंदा निजी विद्यालयों की कथित मनमानी को लेकर प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में निजी विद्यालय द्वारा की जा रही मनमानियों को उजागर किया है। ज्ञापन के बाद एक बार फिर निजी शिक्षा सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है।

कुछ विद्यालय द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर प्रायवेट विद्यालय एसोसिएशन ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन एसडीएम विजय कुमार मंडलोई को दिया। ज्ञापन में उल्लेख है कि कुछ निजी स्कूल संचालकों द्वारा जिम्मेदारों कि मिली भगत से बदनाम रहे परीक्षा केंद्रों को फिर से परीक्षा केंद्र बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे निजी शिक्षा को बदनामी होगी। ज्ञापन में मांग की गई की विगत 10 वर्षों से निजी विद्यालय के परीक्षा केंद्रों पर जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्होंने ने निजी विद्यालयों की शाख पर बट्टा लगाया है। जबकि इस कृत्य में कुछ विद्यालय ही शामिल हैं।

कुछ विशेष विद्यालय द्वारा सभी नियमों को ताक में रखकर मनमाने ढंग से परीक्षा केंद्रों में बदलाव करवाया जा रहा है। संगठन ने मांग की है कि कुछ परीक्षा केंद्रों की सूची नजदीक के शासकीय विद्यालय से दूर के विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उसे मंजूर नहीं किया जाए। यदि ऐसा होता है तो इससे परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

ज्ञापन में वर्ष 2019-20 का जिक्र करते हुए संगठन ने कहा कि इन दूरस्थ परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना घटित हुई थी। जिसके बाद शासकीय शिक्षकों ने वहां ड्यूटी करने से मना कर दिया था। जिसके बाद क्षेत्र के निजी स्कूलों के संचालकों को भी शर्मिंदा होना पड़ा था।

दूर के स्कूल को बनाया जा रहा केंद्र

ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने बताया की खाचरोद में संचालित निजी विद्यालय का निकटतम शासकीय केंद्र खामखेड़ा जत्रा है। जिसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, लेकिन ऐसी कवायद की जा रही है कि खाचरोद के निजी स्कूल का सेंटर रोलागांव बन जाए। जिसकी खाचरोद से दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। वहीं अगर देखा जाए तो मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम लसुड़िया विजय सिंह का शासकीय स्कूल खाचरोद से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। ऐसे में क्या रोलागांव को परीक्षा केंद्र बनाया जाना उचित होगा?

माफिया की गिरफ्त में विभाग

क्षेत्र का शिक्षा विभाग अपनी कारगुजारियों के लिए पहले से ही बदनाम हो चुका है। शिक्षा माफियाओं की गहरे गठजोड़ के कारण प्रतिवर्ष परीक्षाओं के दौरान पूरा विभाग चर्चाओं में आ जाता है। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो केंद्राध्यक्षों पर हमला, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर खामखेड़ा जत्रा में एक कॉलेज के छात्र को एक अन्य स्कूल के छात्र की जगह परीक्षा देते पकड़ा जा चुका है। वहीं पेपर लीक होने जैसे गंभीर मामले भी सामने आ चुके हैं।

नगर के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में देते है परीक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षाएं किस प्रकार संचालित होती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर के छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देते आसानी देखे जा सकते हैं। उत्तीर्ण होने की उम्मीद लगाए बैठे छात्र नगर के विद्यालय में प्रवेश न लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी स्कूलों में प्रवेश लेकर परीक्षा देना पसंद करते हैं। इसका क्या कारण है यह तो शिक्षा विभाग ही सही ढंग से बता सकता है? वहीं निजी विद्यालय को इन परीक्षा केंद्रों का विरोध आखिर क्यों करना पड़ रहा है यह भी एक खोज का विषय है।

समस्याओं की होगी जांच

प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है। जिसमें परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ समस्याएं बताई गई हैं। जिसकी जांच की जाएगी

विजय कुमार मंडलोई, एसडीएम आष्टा

1000 से अधिक विधानसभा क्षेत्र के युवक-युवती ले रहे हैं निःशुल्क प्रशिक्षण

गरीब बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सागर

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा अभिनव योजना चलाकर रहली विधानसभा के युवक-युवतियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण शाला में तैयार कराकर निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। जिससे रहली विधानसभा क्षेत्र के युवक-युवतियों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उत्साह है। वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए मेहनत और लगन के साथ तैयारी में जुटे हुए है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव बताते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए समस्त प्रकार के प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क प्रदान किए जाते हैं । इसी प्रकार पुलिस विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया

जा रहा है इसके लिए उन्होंने स्विमिंग पूल, जिम ,व्यायामशाला को तैयार कराकर युवक-युवतियों को समर्पित की है। भार्गव बताते हैं कि कार्यों की व्यस्तता के चलते समस्त कार्यों का संचालन अभिषेक भार्गव द्वारा संचालित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अभिषेक भार्गव द्वारा प्रदेश एवं देश के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। मंत्री भार्गव द्वारा बनवाए गए स्विमिंग पूल में तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गोपालजी परिसर में एक इंडोर स्टेडियम भी तैयार कराया गया है। मंत्री भार्गव बताते हैं कि गोपाल जी परिसर में आउटडोर स्टेडियम भी तैयार कराया गया है, जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। मंत्री भार्गव ने बताया कि आउटडोर स्टेडियम में पुलिस की तैयारी कर रहे युवक युवतियों के लिए भी विशेषज्ञ द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। जिससे पुलिस विभाग में जाने हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। मंत्री भार्गव ने बताया कि इसके अलावा सर्व सुविधा युक्त साढ़े सात सौ सीटर की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया गया है। ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए कोटिल्य अकादमी के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा निशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है।

इस कोचिंग में रहली विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12 छात्र-छात्राएं निशुल्क कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जिम भी है जिसमें एक्सपर्ट फिटनेस के लिए युवाओं को टिप्स देते हैं और उन्हें सिखाते है। जिम 2969 वर्ग मीटर में फैला है । बिलियड्स खेलने की भी व्यवस्था की गई है । मंत्री भार्गव द्वारा बनवाए गए खेल प्रशिक्षण शाला में खेलों के साथ शतरंज, सांप सीढ़ी, कैरम आदि गेम्स भी होते हैं, डांस क्लास भी तैयार की जा रही है।

कॉलेजों में लगाई गईं थीं बीएसडब्ल्यू की कक्षाएं, भुगतान न होने से फैकल्टी नाराज

अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाकर पेमेंट करना भूला चित्रकूट विश्वविद्यालय

सब रिपोर्टर ॥ भोपाल

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू) की कक्षाएं खत्म होने के डेढ़ साल बाद भी कॉलेज फैकल्टी का भुगतान नहीं किया है। ये कक्षाएं कॉलेजों में हर रविवार को लगाई गई थीं। विश्वविद्यालय की ओर से 500 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से भुगतान करना था। ये कक्षाएं मार्च 2019 से जुलाई तक लगाई गई थीं। शुरुआत में सरकारी स्कूलों में हर रविवार को कक्षाएं लगाने की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थियों की आपत्ति के बाद उच्चशिक्षा विभाग ने कॉलेजों में कक्षाएं लगाए जाने के निर्देश दिए थे।

दरअसल जनअभियान परिषद की ओर से बेरोजगार युवाओं को समाजसेवा की धारा से जोड़ने के लिए

एनजीओ के माध्यम से एकजुट किया गया, फिर उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाया। एकजुट होने वाले सभी ग्रामीण युवाओं का एक ही लक्ष्य था, समाज में सुधार लाना। चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। इस लक्ष्य को लेकर जिन युवाओं ने हायर सेकंडरी परीक्षा पास की थी और वे सोशल वर्क से जुड़े थे, ऐसे युवाओं को तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है। इसके लिए 45 वर्ष तक के पुरुष और महिलाओं को कोर्स कराने चित्रकूट यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा विभाग से जोड़ा गया। तीन साल तक कोर्स करने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाई जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने चित्रकूट विवि के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कॉलेज प्रोफेसर या अतिथि विद्वानों को दायित्व दिया है। विद्यार्थियों के अनुसार बीएसडब्ल्यू के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 6-6 प्रश्न-पत्र सहित कुल 18 प्रश्न-पत्र हैं। प्रत्येक प्रश्न-पत्र की 40 कक्षाएं लगना जरूरी होता है। इस तरह 18 प्रश्न-पत्रों के लिए कुल 40 रविवार में 720 कक्षाएं होती हैं। सत्र 2018-19 में 17 रविवार को प्रत्येक केंद्र पर 18 प्रश्न-पत्र के लिए 306 कक्षाएं लगाई गई हैं।

यूजीसी के निर्देश- 2022 से पहले भर्ती करें यूनिवर्सिटी

आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने विश्वविद्यालयों ने लिखा शासन को पत्र

सच रिपोर्टर ॥ भोपाल

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गंभीरता से लिया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाओं को 2022 से पहले शुरू करें, अन्यथा यूजीसी गंभीर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगी।

यूजीसी ने पूर्व में विवि को पद भरने के लिए दिसंबर 2020 तक का समय दिया था, लेकिन प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कारण भर्ती के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। विवि में यूजीसी ने एक साल में मोहलत मांगी थी, जिस पर यूजीसी ने 2022 से पहले भर्ती करने को कहा है। यूजीसी ने कुलपतियों को लिखे गए पत्र में कहा है कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी गंभीर चिंता का विषय है और इसका समाधान अतिशीघ्र निकालने की जरूरत है। आपको एक बार पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि शिक्षकों की बहाली से संबंधित प्रक्रियाओं को गंभीरता से शुरू करें और 2022 से पहले यूजीसी के एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर इसे अपडेट करें। यूजीसी के लेटर के बाद विवि ने सरकार को पत्र लिखकर जल्दी से जल्दी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। ज्ञात हो कि कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को यूजीसी तभी अनुदान देगा जबकि उनके पास अपने पर्याप्त संसाधन होंगे।

80 फीसदी पद खाली

विश्वविद्यालयों में भर्ती न होने के कारण 80 फीसदी पद खाली हैं। इन पदों पर या तो प्रतिनियुक्ति या अतिथि शिक्षकों को रखकर काम चलाया जा रहा है। विवि में पद खाली होने के कारण सभी सुविधाओं के बाद भी नैक से ए या ए प्लास ग्रेड मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इस कारण रूसा सहित अन्य संस्थानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ भी विश्वविद्यालयों को नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा जारी रोस्टर में एसटी को 20 प्रतिशत, एससी को 16 प्रतिशत एवं ओबीसी के लिए 27 फीसदी सीटें रिजर्व की हैं, जबकि हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षक के मामले को खारिज कर दिया था, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहीं रोस्टर में सवर्ण आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। विवि ने शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है।

छात्रों और अभिभावकों को परेशान करने के मामले पर हाईकोर्ट गंभीर

सागर पब्लिक स्कूल के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस

» पांच अन्य स्कूलों के प्राचार्यों से भी पूछा, क्यों न हो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई

सच संवाददाता ॥ जबलपुर

कोराना संक्रमण काल में स्कूलों की फीस को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान किए जाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल में दो बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किये जाने को न्यायालय की अवमानना बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने स्कूल के चेयरमेन सहित सभी छह स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है, कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।यह अवमानना याचिका माय पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट प्रमोद प्रियदर्शी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है, कि कोरोना काल में स्कूलों की फीस को लेकर दायर मामलों में न्यायालय ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिये थे।

शासन ने भी फीस देरी पर किसी भी बच्चे को स्कूल और परीक्षा से वंचित ना किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये थे। हाल ही में भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल में दो छात्रों को फीस में हुई देरी पर ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया था। जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित मंत्री तक से की गई। दायर मामले में कहा गया कि फीस के लिये बच्चों के साथ किया गया स्कूल प्रबंधन का व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवेहलना है। मामले में सागर पब्लिक स्कूल के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल, साकेत नगर स्कूल प्रिंसिपल पंकज शर्मा, कटरा हिल्स की प्रिंसिपल प्राची वर्मा और गांधीनगर की प्रिंसिपल मिस अल्पना प्रभु सहित दो अन्य सागर पब्लिक स्कूल के प्राचार्यों को पक्षकार बनाया गया है।

भास्कर

केन्द्रीय विद्यालय मुंगावली

पिपरई रोड, मुंगावली, जिला-अशोकनगर, म.प्र. 473443

ई-मेल : ppl.moongawali@kvs.gov.in वेबसाइट: mungaoli.kvs.ac.in

वाक-इन-इंटरव्यू (Walk In Interview) सूचना

शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर 18 से 65 आयुवर्ग के शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है। इस हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी केन्द्रीय विद्यालय मुंगावली की वेबसाइट mungaoli.kvs.ac.in पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरकर, स्वयं के मूल शैक्षणिक दस्तावेजों एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों सहित उक्त साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हो सकते है। पी.जी.टी. एवं टी.जी.टी. शिक्षक हेतु दिनांक 04.03.2021 को प्राथमिक शिक्षक हेतु दिनांक 05.03.2021 को एवं योग प्रशिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एवं नर्स(महिला) हेतु दिनांक 06.03.2021 को प्रातः 09.00 बजे से वाक-इन-इंटरव्यू आयोजित किये जायेंगे। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र के लिए विद्यालय की वेबसाइट mungaoli.kvs.ac.in का अवलोकन करें।

प्राचार्य
के.वि. मुंगावली

केन्द्रीय विद्यालय गुना
Kendriya Vidyalaya
nanakhedi Guna (M.P.) 473001

PHONE NO. 07542-268641 (O)
E-MAIL
ppl.guna@kvs.gov.in
WEBSITE
https://guna.kvs.ac.in

फा. 2-10/2020-21/अनु.साक्षात्कार/केविगु/

दिनांक 23/02/2021

वाक इन इंटरव्यू

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान केंद्रीय विद्यालय गुना में पूर्णतः अंशकालीन संविदा अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए दर्शायी गयी तिथि एवं समय पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के सीधे साक्षात्कार द्वारा विद्यालय में पैनल तैयार किया जाना है;

क्रमांक	पद	साक्षात्कार तिथि	पंजीकरण का समय
01	स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान	24/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
02	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा	24/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
03	प्राथमिक शिक्षक	24/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
04	वोकेशन इंस्ट्रक्टर खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, संगीत एवं नृत्य, आर्ट एवं क्राफ्ट	25/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
05	काउंसलर	25/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
06	कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर	25/03/2021	प्रातः 09:00 बजे से 10.00 बजे तक
07	डॉक्टर	25/03/2021	
	नर्स		

नोट :- 01. आवेदक का रजिस्ट्रेशन उक्त तारीक को ऊपर बनी टेबल में दर्शाए अनुसार किया जावेगा। स्वयं का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चस्पा करें और दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न कर दस्तावेजों की मूलप्रतियों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित हो शैक्षणिक योग्यता तथा मानदेय विद्यालय की वेबसाइट https://guna.kvs.ac.in पर उपलब्ध हैं। 02. आयु सीमा 01.04.2021 को 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। 03. उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार हेतु स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना है। 04. उक्त पद पर अंशकालीन संविदा अनुबंधन के आधार पर है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार से नियमित नियुक्ति का दावा केंद्रीय विद्यालय संगठन में नहीं कर सकेंगे। 05. रिक्त पद भर जाने अथवा अवकाश से शिक्षक के लौट आने पर नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जायेगी। 06. चयनरोपरान्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती है। 07. चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन कराकर विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(श्री मोहम्मद तनवीर)
प्रभारी प्राचार्य

अपराध से नाता तोड़ा • तीन साल में सुखराम पर सट्टा एक्ट के कई मामले हुए दर्ज, जुर्माना भरने से केस हुए खत्म

पिता के सट्टा खिलाने पर बेटियों को स्कूल में महसूस होती थी शर्मिंदगी, एसपी को शपथ-पत्र देकर पिता ने कहा- मैं अब सट्टा नहीं खिलाऊंगा

भास्कर संवाददाता | सागर

बेटियों को स्कूल में शर्मिंदगी महसूस न हो और पत्नी मोहल्ले की अन्य महिला के साथ सम्मान से रह सकें। इसके लिए गोपालगंज क्षेत्र में रहने वाले सुखराम अहिरवार ने अपराध से अपना नाता तोड़ दिया। उसने पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के नाम एफिडेविट देकर अब सट्टा न खिलाने की शपथ ली है। सुखराम को अपराध की दुनिया से बाहर निकलने की प्रेरणा उसकी दोनों बेटियों व पत्नी से मिली। बीए तक पढ़े सुखराम से उसकी दोनों बेटियों ने कहा कि पापा सट्टा खिलाना अच्छी बात नहीं है। घर पर पुलिस के आने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। इसके बाद सुखराम का मन बदल गया और बेटियों की बात मानते हुए अपराध को छोड़ने का संकल्प लिया।

नौकरी नहीं लगी तो सट्टा की लेने लगे बुकिंग

सुखराम अहिरवार ने बताया कि बीए तक पढ़ाई करने और शादी होने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली। तो परिवार को चलाने के लिए वह सट्टा खिलाने लगे। शादी के बाद कुछ दिन सुखराम ने सब्जी बेची, हाथ ठेले पर मजदूरी की, मूंगफली का ठेला भी लगाया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। दो बेटियां होने के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्च व परिवार के अन्य खर्च भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहे थे। इससे बुरी संगत में फंस गए।

सागर | टीआई उपमासिंह को शपथ पत्र देते हुए सुखराम।

मां-बाप गुजर जाने के बाद भैया-भाभी ने पाला

सुखराम ने बताया कि जब वह 8 साल के थे। तब उनके माता-पिता शांत हो गए। इसके बाद बड़े भैया और भाभी ने ही उन्हें पाला, अपने साथ रखा, बीए तक पढ़ाई कराई और फिर शादी भी कराई। 10वीं पास करते ही सुखराम नौकरी की तलाश करने लगे, लेकिन किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया और नौकरी नहीं मिली।

सुखराम पर सट्टा एक्ट के कई मामले हुए दर्ज

सुखराम ने बताया कि वे करीब 3 साल से सट्टा की बुकिंग ले रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ गोपालगंज थाने में सट्टा एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हुए। इनमें जुर्माना भरकर वे छूट गए। कई बार उनके घर पर भी पुलिस आई। उनकी वजह से पूरे परिवार ने शर्मिंदगी महसूस की। अब सुखराम का कहना है कि वे मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने घर में ही एक किराने की दुकान भी खोल ली है।

दो व्यवस्था दो स्वरूप • कॉलेजों में 20 जनवरी से यूजी-पीजी की ऑफलाइन कक्षाएं लग रही हैं

अग्रणी में 24% व गर्ल्स कॉलेज में 37% विद्यार्थी की उपस्थिति, विवि की ऑनलाइन कक्षाओं में 64% हाजिरी

भास्कर संवाददाता | सागर

जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों में दो तरह से पढ़ाई हो रही है। डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में जहां ऑनलाइन क्लास लग रही हैं। वहीं छतरपुर विवि से जुड़े कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। इसके दो स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं। ऑफलाइन कक्षाओं में जहां कम उपस्थिति देखने को मिल रही है। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में छात्र जुड़कर पढ़ रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज में जहां 37% छात्राएं कक्षाओं में पहुंच रहीं हैं। वहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स अग्रणी कॉलेज में महज 24% विद्यार्थी ही कॉलेज पहुंच रहे हैं। वहीं डॉ. हरीसिंह गौर विवि की ऑनलाइन कक्षाओं में 64% तक विद्यार्थी जुड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

सागर। अग्रणी कॉलेज में कक्षा में कम ही विद्यार्थी पढ़ने आए।

प्राचार्य बोले : कॉलेजों में धीरे-धीरे बढ़ रही है उपस्थिति, ग्रामीण अंचल के छात्र नहीं आ पा रहे हैं

गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बीडी अहिरवार ने बताया कि कॉलेज में औसतन 30 से 50% छात्राएं विभिन्न कक्षाओं में उपस्थित हो रही हैं। धीरे-धीरे छात्राओं की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हम उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अग्रणी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जीएस रोहित ने बताया अभी सीसीई एग्जाम चल रहे हैं। इस कारण से सिर्फ वे ही छात्र कॉलेज आ रहे हैं, जिनका एग्जाम होता है। फिर भी विभिन्न कक्षाओं में 20 से 35% तक छात्र उपस्थित हो रहे हैं। ग्रामीण अंचल के कुछ छात्र वाहनों की कमी या फिर कोरोना के डर के कारण क्लास में नहीं आ रहे हैं। फिर भी उपस्थिति अब लगातार बढ़ ही रही है।

मार्च से प्रैक्टिकल की कक्षाएं ऑफलाइन लगेंगी

सागर विवि के डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एएन शर्मा ने बताया कि हमारे यहां पीजी की कई कक्षाओं में उपस्थिति 90 से 100% तक हो रही है। हालांकि यूजी में कुछ क्लासों में छात्र कम आ रहे हैं। फिर भी विवि में ओवरऑल 60 से 70% छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। विवि में मार्च से प्रैक्टिकल ऑफलाइन कराने पर विचार चल रहा है। जल्दी ही इस मामले में प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ऑफलाइन कक्षाओं के संबंध में जो भी निर्देश यूजीसी से आएंगे, उसी के अनुसार प्रशासन निर्णय लेगा।

हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्य की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

अतिरिक्त कक्षा लगाने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| माखननगर

मंगलवार को शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड के समस्त हाई हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा की व सभी प्राचार्यों से कहा कि बालकों से संपर्क कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किए जाएं। रविवार व अन्य कार्य दिवसों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर कोर्स पूर्ण किया जाए जिला कार्यालय से समीक्षा बैठक हेतु पधारे आरके गुप्ता, एडीसी विनोद तिवारी, एडीपीसी विकास खंड शिक्षा अधिकारी अर्चना मिश्रा द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय की नवीन व्यवसाई का प्रयोगशाला आईटी एवं हार्डवेयर की लैब का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। अधिकारियों ने नवीन लैब की तैयारी देखकर दोनों अधिकारियों ने प्रशंसा की। इस अवसर पर प्राचार्य जीएस ठाकुर निधि दुबे, सुनील शर्मा आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे।

11 केबी के तार में चिपका मिला उल्लू

सेमरी हरचंद। होशंगाबाद पिपरिया मार्ग के मध्य सेमरी हरचंद के पास शिवपुर सब माइनर पर मुकेश अग्रवाल के खेत से निकल रही 11 केवी के तारों में मंगलवार सुबह 9 बजे सुनहरी कलर का उल्लू चिपका मिला। खेत की लाइन बंद होने पर कृषक ने विद्युत विभाग में जानकारी दी तब विभाग के कर्मचारी राजू मौर्य, सलमान खान, राजू ऊईके फाल्ट ढूंढते हुए उक्त स्थान पर पहुंचे यहां फाल्ट मिला लाइनमैन ने ऊपर खंबे पर चढ़कर देखा तो उसको सुनहरे कलर का उल्लू चोंच में चूहे को दबाए हुए मृत अवस्था में मिला जिसको उन्होंने तार से निकालकर नीचे पटक दिया और अपना फाल्ट सुधार कर विद्युत कार्यालय वापस आ गए।

आरोपियों ने बना रखी थी नीट से मिलती जुलती वेबसाइट

मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पर 172 छात्रों को ठगा, तीन गिरफ्तार

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रों को ठगने वाले तीन आरोपियों को सायबर क्राइम भोपाल ने गिरफ्तार किया है। उनसे 15 कम्प्यूटर, 12 लैपटॉप, 27 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने नीट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई और ठगी के लिए कॉल सेंटर खोल रखा थी। जांच में देशभर के 172 छात्रों के साथ ठगी की जानकारी मिली है। इसमें 26 मप्र और 24 छात्र महाराष्ट्र के हैं।

एएसपी सायबर क्राइम अंकित जायसवाल ने बताया कि मामले की शिकायत पिछले दिनों एक छात्र ने की थी। उसने बताया कि इंदौर स्थित नीट काउंसलिंग नामक कंपनी ने उससे संपर्क किया और मेडिकल में प्रवेश कराने का आश्वासन दिया। उसने भोपाल के एमपी नगर स्थित होटल में कंपनी के लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने कंपनी के दो बैंक अकाउंट में रुपये जमा करवाए। बाद में कंपनी के लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए।

ठगी के आरोपियों से बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन।

सीसीटीवी से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

फरियादी को जिस होटल में मिलने के लिए बुलाया गया था, वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो एक महिला के फुटेज मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी अरविंद कुमार उर्फ आनंद राव को पुणे महाराष्ट्र, आरोपी राकेश कुमार और अनामिका (परिवर्तित नाम) को इंदौर से गिरफ्तार किया। विजय नगर इंदौर स्थित उनके कॉल सेंटर पर छापा मारा।

ठगी के शिकार छात्रों से संपर्क कर रही पुलिस

आरोपियों के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर ठगी के शिकार हुए छात्रों से पुलिस संपर्क कर रही है। उनके मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि अब तक आरोपियों ने कितने लोगों से कितनी रकम ठगी है। जांच में पिछले एक साल के दौरान करीब एक करोड़ रुपए ठगे जाने का अनुमान है। जालसाजों ने बेंगलुरू, पुणे और इंदौर में अपने कार्यालय खोल रखे थे।

सरगना ने हैदराबाद से किया है एमटेक

एएसपी जायसवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी अरविंद कुमार बेंगलुरू का रहने वाला है। उसने हैदराबाद के उस्मानिया कालेज से एमटेक किया है और गोल्ड मेडलिस्ट है। वह बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और दो सालों से इंदौर में रह रहा था। यहीं उसकी पहचान एमबीए कर चुके राकेश और पैरामेडिकल का कोर्स कर चुकी अनामिका से हुई थी। इन्होंने कई युवाओं को कॉल सेंटर पर रखा था।

50 हजार रुपए में देते थे एडमिशन की गारंटी

डीएसपी सायबर क्राइम नीतू सिंह ने बताया कि आरोपियों ने शासन से मिलती-जुलती नीट काउंसलिंग डॉट कॉम नाम से फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। नेट पर मौजूद सैकड़ों वेबसाइटों पर सर्च करने वाले छात्रों का डेटा चोरी कर वह अपनी साइट पर डाल लेते थे, जिससे छात्रों को भरोसा हो जाता था। वे 5 हजार लेकर काउंसलिंग करते थे। 25 हजार में एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया करते थे। 50 हजार में वे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की गारंटी देते थे।

भवन की मरम्मत कराए बिना राशि का कर लिया आहरण

बालिका छात्रावास में शासन की राशि का किया जा रहा भ्रष्टाचार

पीपुल्स संवाददाता • सागर/देवरी
मो.नं. 9826021098

महाराजपुर पंचायत में बने शासकीय माध्यमिक कन्या छात्रावास में करीब 50 बच्चियों की दर्ज संख्या है। शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान तहत कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक की ग्रामीण की बच्चियों के लिए ठहरने छात्रावास बनाया गया था। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां स्कूल के पास छात्रावास में ही रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्हें कोई भी परेशानी न हो।

शासन द्वारा छात्रावासों में लाखों रुपए खर्च कर छात्राओं के रहने-खाने आदि की सुविधा दी जाती है। मगर शासन की योजना, नियमों को ताक पर रखकर महाराजपुर के माध्यमिक छात्रावास की अधीक्षक बच्चियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए राशि में ही भ्रष्टाचार कर रही है। छात्राओं के परिजनों द्वारा बताया गया कि छात्रावास भवन मरम्मत के लिए 1.50 लाख की राशि शासन से मिली थी। भवन में कोई मरम्मत नहीं कर राशि का आहरण कर लिया गया। रिकार्ड में भवन की मरम्मत होना बता दिया गया। इसी तरह छात्रावास में नल फिटिंग के लिए करीब 33 हजार की राशि आई थी। जिसका भी बिना कार्य किए आहरण कर लिया गया। छात्रावास पुताई हेतु करीब 1 लाख की राशि शासन द्वारा दी गई थी। मगर उस राशि में भवन में एक या दो दीवार की बस पुताई करवा दी। पूरी राशि निकालकर भवन की पुताई बताई गई है।

छात्रावास अधीक्षक अर्चना व्यास पर छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक छात्रावास में कई अनियमितता करती है। बच्चियों को शासन की कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। छात्रावास में जब कोई जांच करने आता है तो बच्चियां जब अधिकारी से शिकायत करती है तो अधीक्षक द्वारा उन्हें छात्रावास से भगा देने की धमकी दी जाती है। साथ ही कहा जाता है कि उनकी जिले के अधिकारियों से सांठगांठ है। शिकायत से भी कुछ नहीं होगा। जो भी शिकायत करेगा उसे छात्रावास में नहीं रहने दूंगी।

कार्रवाई की जाएगी

महाराजपुर माध्यमिक कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर जांच करेंगे। यदि अधीक्षक द्वारा वहां के कार्यों की राशि में भ्रष्टाचार किया गया होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा। इस प्रकार के कार्य करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

– आरसी मिश्रा, जेंडर प्रभारी, जिला शिक्षा केन्द्र, सागर

आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने कलेक्ट्रेट में लगाए नारे

युवाओं को सता रहा ओवरएज होने का डर, ज्ञापन सौंपकर की भर्ती शुरू कराने की मांग

पीपुल्स संवाददाता • सीहोर

मो.नं. 9425008066

मिलेंट्री ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे जिले के सात हजार युवाओं को ओवरएज होने का डर सता रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर ने भोपाल संभाग की भर्ती की घोषणा अब तक नहीं है। परेशान आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में नारे लगाए और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कोरोना के कारण स्थागित भर्ती जल्दी शुरू कराने की मांग की।

आर्मी में जाने की बीते साल से तैयारी कर रहे युवा छात्रों का कहना था की माऊ और ग्वालियर की भर्ती आ चुकी है लेकिन भोपाल संभाग की भर्ती को रोक लिया गया है। अगर समय पर भर्ती नहीं होती है तो हम ओवरएज हो जाएंगे और आर्मी में कभी भी भर्ती नहीं हो पाएंगे। युवाओं ने जिला प्रशासन सेआर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस से चर्चा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रोहित पाटीदार, अंकित मीणा, विजय सेन, देवेंद्र भाई, नीरज चौहान, सोनू राय, मंगलेश, अभिषेक मीणा, वीर मालवीय, लोकेंद्र, लखन वर्मा, सचिन, विकास मीणा, अंकुर वर्मा, विजेंद्र, जसपाल सिंह, अरुण परमार, आकाश, नरेंद्र, जितेंद्र, संजय केसरिया, जगदीश धनगर, विशाल आदि शामिल हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नवोदय विद्यालय के लिए छात्र-छात्राओं ने दी प्रवेश परीक्षा

पीपुल्स संवाददाता • सीहोर
मो.नं. 9425008066

जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर में कक्षा 9वीं के लिए छात्र-छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा दी। इसमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए पूर्ण एहतियात और सुरक्षा का ध्यान रखा। विद्यालय प्राचार्य गीतिका शर्मा एवं उप प्राचार्य प्रीता खत्री ने छात्रों को समझाइश दी गई कि छात्र मास्क लगाकर ही विद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे। छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था में भी निश्चित दूरी का ध्यान रखा गया।

परीक्षा प्रभारी परमेश्वर भट्ट, महेश कुमार पाल, मनीष मालवीय द्वारा सभी पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें कहा गया कि ओएमआर शीट, रोल नंबर एवं नाम छात्र-छात्राओं से स्पष्ट रूप में लिखें एवं एवं रोल नंबर के अनुसार छात्र-छात्राओं को बैठाएं। मात्र 2 सीटों के लिए 1320 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। जिसमें से चार सेंटर बनाए गए। हायर सेकंडरी स्कूल श्यामपुर, हायर सेकंडरी स्कूल दोराहा, हायर सेकंडरी स्कूल झारखेड़ा, जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर में 422 छात्र-छात्राओं को आना था। जिसमें से 270 छात्र ही सम्मिलित हो सके। 152 छात्र अनुपस्थित रहे। स्टाफ नर्स कविता ने सभी का तापमान चेक किया।

ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप फोटो में पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर रोहित पंडित, कुलपति डॉ. राजेश कपूर , चेयरमैन एमपीपीयूआरसी डॉ. भरत शरण सिंह, ईसी मेंबर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉ. अशोक खंडेलवाल और रजिस्ट्रार डॉ. नीरजा मलिक व अन्य स्टाफ मेंबर्स।

पीपुल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन

80 स्टूडेंट्स बने डेंटिस्ट, मेडल और उपाधि मिली

रिपोर्टर • IamBhopal

Mobile no. 9827080406

पीपुल्स विश्वविद्यालय भोपाल के पीपुल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में 80 डॉक्टर्स को उपाधि दी गई । पीपुल्स विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉ नीरजा मलिक ने चेयरमैन एमपीपीयूआरसी भरत एस. सिंह का स्वागत किया। पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर रोहित पंडित ने ईसी मेंबर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉ. अशोक खंडेलवाल का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। पीपुल्स विश्वविद्यालय और पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर रोहित पंडित ने सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स व उनके अभिभावकों को संबोधित किया। समस्त डॉक्टर्स को सेरेमनी शपथ कुलपति डॉ. राजेश कपूर द्वारा दिलाई गई।

पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर रोहित पंडित डॉ. सिद्धार्थ मोदी को सम्मानित करते हुए।

स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हुए चेयरमैन एमपीपीयूआरसी डॉ. भरत शरण सिंह और डॉ. अशोक खंडेलवाल ।

कुलपति डॉ. राजेश कपूर ने किया स्वागत

डीन पीपुल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर डीन डॉ. परमिला कुलकर्णी ने डॉ .अशोक खंडेलवाल व पीपुल्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश कपूर ने मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के डॉ. भरत शरण सिंह को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया।

डेंटिस्ट्स को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भरत सिंह और डॉ अशोक खंडेलवाल ने समस्त डेंटिस्ट डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया इसी रूपरेखा में संस्था के कुलपति डॉ .राजेश कपूर, कुलसचिव डॉ नीरजा मलिक और पीपुल्स ग्रुप के डायरेक्टर रोहित पंडित ने समस्त डेंटिस्ट डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह और मेडल देकर उनका उत्साह दोगुना किया।

समाजसेवा पर भी डॉक्टर्स ध्यान दें

डॉ. अशोक खंडेलवाल ईसी मेंबर डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने सीधी में घटित घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को कई रोचक जानकारी प्रदान की। श्री सिंह ने अपने शब्दों में डेंटिस्ट की भूमिका का पालन करते हुए एक अच्छे डॉक्टर और ओरल सर्जरी ओरल कॉस्मेटिक की ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ में उन्होंने डॉक्टर्स से अपने विचारों को भी साझा किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करते हुए समाज सेवा करने की भी अपील की। कार्यक्रम में संस्था के समस्त डायरेक्टर प्रिंसिपल और शिक्षक गण एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए।

छात्रों ने परीक्षा में फर्जीवाड़े के विरोध में रैली निकाली

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

कृषि छात्रों ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ) और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एसएडीओ) पदों की परीक्षा में फर्जीवाड़े के विरोध में बुधवार को कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज से मेला ग्राउंड तक रैली भी निकाली। प्रदेश सरकार के कोई एक्शन नहीं लेने पर छात्र गांधी के तीन बंदर भी बने। छात्र सुदीप बिलगनिया का कहना है कि फर्जीवाड़े की जांच होने तक विरोध प्रदर्शन चलेगा। गुरुवार को कॉलेज में तालाबंदी की जाएगी। बता दें कि कृषि विभाग में आरएईओ की भर्ती 6 साल और एसएडीओ के 10 साल बाद आई है। पीईबी ने पदों के लिए परीक्षा 17 फरवरी 21 को कराई थी।

90 कॉलेजों ने मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा किया है, जांच हो

एनएसओ ने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के नाम ज्ञापन सौंपा

ग्वालियर। नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिह गुर्जर के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के नाम ज्ञापन बुधवार को एसडीएम अनिल बनवारिया को सौंपा। संगठन ने ज्ञापन के जरिए कहा है कि ग्वालियर जिले से सत्र 2020-21 में 90 कॉलेजों ने मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा किया है। आवेदन में फर्जी हॉस्पिटल, बिल्ड़िग का सहारा लिया गया है। छात्र नेता ने एसडीएम को बताया कि जयश्री श्याम कॉलेज ने बिल्डिग किराए पर ले रखी है। कॉलेज में बीएड, डीएलएड, जीएनएम कोर्स संचालित है, लेकिन न तो हॉस्पिटल है और न स्टाफ। कॉलेज का फिर से निरीक्षण कराया जाए। इसके बाद ही कोर्स संचालन की अनुमति दी जाए। नर्सिंग काउंसिल कॉलेजों की सही तरीके से जांच कराए बिना मान्यता देती है तो संगठन छात्रहित में आंदोलन करेगा।

350 प्राध्यापकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी

गुस्सा ● 10 साल से पदोन्नति नहीं होने से है नाराजगी, प्रदेश सहित राजधानी के भी प्रोफेसर हैं शामिल

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के 350 से अधिक प्रोफेसरों (प्राध्यापक) ने शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। यह आवेदन पिछले एक साल में आए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने वालों में ज्यादातर वह प्रोफेसर हैं, जिनकी सेवा के एक-दो साल बचे हैं। इसमें राजधानी के भी पांच प्रोफेसर शामिल हैं।

प्रोफेसरों का कहना है कि हमें करीब दस साल से पदोन्नति नहीं दी गई। अब एक या दो साल के अंदर शासन पदोन्नति देने वाला भी नहीं है। इस कारण अब घर में रहकर पेंशन लेना ही सही है। उधर, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी के कारण हर शिक्षक पर कार्य का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सेवानिवृत्ति लेने का एक कारण यह भी सामने आया है।

515 सरकारी कॉलेजों की संख्या प्रदेश में	**471** कॉलेजों में कितने प्रभारी प्राचार्य
394 यूजी कॉलेज प्रदेश के प्राचार्य विहीन	**77** पीजी कॉलेज प्रदेश के प्राचार्य विहीन
7500 कॉलेजों में प्रोफेसरों की संख्या प्रदेश में	**12** लाख (करीब) यूजी व पीजी के विद्यार्थी

कॉलेजों में 2010 के बाद से प्रोफेसरों को पदोन्नति नहीं दी गई है। इसका कारण आरक्षण और एकेडमिक ग्रेड-पे को लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित होना है। इस कारण भी एक-दो साल में सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसरों का मन अब पढ़ाने में नहीं लग रहा है। साथ ही प्रोफेसरों के एरियर्स के भुगतान में भी देरी हो रही है, जबकि यह प्रोसेस 31 मार्च के बाद तेज हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के बाद दस साल से दे रही हैं सेवा: दूसरी तरफ एक प्रोफेसर सेवानिवृत्ति के बाद करीब दस साल से सेवा दे रही हैं। मूलतः कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद हिंदी की प्रोफेसर डॉ. आभा वाजपेयी करीब आठ साल तक इसी कॉलेज में पढ़ाती रहीं। इसके बाद 2018 से सत्यसाईं कॉलेज में स्वयंसेवी सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। कॉलेज में परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है।

उनका कहना है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद घर में खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगा। डॉ. वाजपेयी इन कार्यों के लिए आने-जाने का ही खर्च लेती हैं।

> लंबे समय से न तो पदोन्नति मिली है और न ही कैरियर एडवांसमेंट दिया गया। इससे प्रोफेसर कुंठाग्रस्त हो गए हैं। इस कारण प्रदेश के करीब 350 से अधिक प्रोफेसरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है।
>
> **- आनंद शर्मा**, महासचिव, मप्र प्राध्यापक संघ

> यह हर साल की प्रक्रिया है। अगर इस साल सेवानिवृत्ति लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो प्रोफेसरों का अपना निजी कारण रहा होगा।
>
> **- अरुण राजन**, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

मप्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन

भोपाल (नयदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से फिर बात की। इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर व छिंदवाड़ा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसलिए प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के मजदूर काम करने के लिए अन्य राज्य न जाएं, उन्हें मनरेगा के तहत गांव में ही काम दिलाया जाएगा। उन्होंने सभी से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की।

मुख्यमंत्री शिवराज का फाइल फोटो

सीएम ने की समीक्षा

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए की समीक्षा
- प्रदेश में ही दिलाएंगे काम, मजदूरी के लिए न जाएं बाहर
- इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर और छिंदवाड़ा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश

लगातार निगरानी हो

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, वहां सावधानी बरती जाए। वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी सतर्कता बरतें। प्रभार वाले जिलों की लगातार निगरानी हो। जागरूकता के लिए कलेक्टर अभियान चलाएं। रोको-टोको की रणनीति अपनाई जाए।

महाराष्ट्र से आने वालों की जांच

बताया गया कि बालाघाट, सिवनी, बैतूल आदि सीमावर्ती जिलों से मजदूर प्रतिदिन महाराष्ट्र काम करने के लिए जाते हैं। इन्हें गांव में ही मनरेगा के तहत काम दिलाया जाए। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच प्रदेश की सीमा पर अनिवार्य रूप से की जाए। कोरोना निगेटिव को ही प्रवेश दिया जाएगा।

मेडिकल की सीट दिलाने का झांसा देने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने बुधवार को एक ऑनलाइन कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से नीट में मिले अंकों के आधार पर देशभर के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवाने का झांसा देते थे। प्रवेश के नाम पर यह गिरोह पांच हजार से दो लाख तक की रकम एक छात्र से ले लेता था। गिरोह का सरगना अरविंद कुमार उर्फ आनंद राव उस्मानिया विश्वविद्यालय में एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। इंदौर के विजय नगर निवासी राकेश कुमार और अनामिका (परिवर्तित नाम) को भी गिरफ्तार किया गया है।

साइबर क्राइम ब्रांच की डीएसपी नीतू ठाकुर के अनुसार जनवरी 2021 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले कार्तिक नाम के एक छात्र ने शिकायत की थी कि उसे एक फोन

साइबर क्राइम भोपाल ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

प्रवेश दिलवाने के लिए जमा करवा लेते थे हजारों रुपये

आया और अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने के नाम पर भोपाल में एक होटल में बुलाया गया था। जहां उससे दो लाख रुपये जमा करवाए गए। रुपये लेने के बाद आरोपितों ने अपना फोन बंद कर लिया था। बाद में छात्र ने स्वजनों के साथ भोपाल आकर साइबर सेल में शिकायत की थी। मोबाइल नंबर और वेबसाइट wwwneetcouselling.com के माध्यम से साइबर सेल की टीम बेंगलुरु (कर्नाटक) में रहने वाले अरविंद कुमार उर्फ आनंद राव के ठिकाने पर पहुंची और गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। **पेज >> 3 भी पढ़ें**

इग्नू ने शुरू किया मास्टर डिग्री प्रोग्राम

एजुकेशन अपडेट

लेक सिटी रिपोर्टर। इंदिरा गांधी मुक्त विवि (इग्नू) ने एंवायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थी 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के अलावा एक समग्र, वैज्ञानिक और स्थायी पर्यावरण प्रबंधन को पढ़ाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम सामाजिक-आर्थिक कारणों और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण और गिरावट की विशेषताओं को एक अंतर्दृष्टि देगा। इसमें मानव, वायुमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य जीवों पर प्रभाव शामिल है। आवेदन ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए निर्धारित योग्यता विज्ञान विषय से स्नातक होना आवश्यक है।

एआईसीटीई के पीजी प्रोग्राम के लिए आवेदन 28 तक

● लेक सिटी रिपोर्टर ●

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) की पीजी प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 फरवरी तक जारी रहेगी। स्टूडेंट्स ऑफिशियल पोर्टल www.aicte-india.org पर आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को हर महीने 12,400 रुपए मिलेंगे।

यह स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो गेट या जीपीएटी परीक्षा क्वालिफाई हैं और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और मास्टर ऑफ फॉर्मेसी में फुल टाइम स्कॉलर हैं।

जिला शिक्षा केन्द्र के भंडारी को कलेक्ट्रेट की स्थापना शाखा का प्रभार

प्रतिबंध के बावजूद आखिर संविदा कर्मचारी का अटैचमेंट क्यों?

स्टार समाचार सतना

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का दूसरे विभाग पर अटैचमेंट पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद जिला शिक्षा केन्द्र के एक लिपिक पिछले पांच सालों से कलेक्ट्रेट में अटैच हैं। संविदा के लिपिक को वर्तमान में कलेक्ट्रेट की प्रमुख शाखाओं में से एक स्थापना शाखा का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले ये कलेक्टर के स्टेनों नम्बर दो थे। अटैचमेंट में जिला शिक्षा केन्द्र से कलेक्ट्रेट आए संविदा के लिपिक प्रमोद द्विवेदी को स्थापना शाखा का प्रभारी बनाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर संविदा के लिपिक में ऐसी क्या योग्यत है जो

हस्ताक्षर जिला शिक्षा केन्द्र में

बताया जाता है कि प्रमोद द्विवेदी की मूल पदस्थापना जिला शिक्षा केन्द्र में है। यहां इनके पास भंडार का प्रभार है। पर पिछले कई सालों से वे कलेक्ट्रेट में अटैच हैं। कलेक्ट्रेट में अटैच होने के बावजूद कागज में आज भी इन्हीं के पास जिला शिक्षा केन्द्र के भंडार का प्रभार है। श्री द्विवेदी भले ही अपनी सेवाएं कलेक्ट्रेट में दे रहे हों पर इनकी तनख्वाह अभी भी जिला शिक्षा केन्द्र से ही बनती हैं। अब सवाल यह है कि बैन होने के

सिंहपुर में पदस्थापना, शिकायत शाखा में काम

ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमोद द्विवेदी भर ही कलेक्ट्रेट में अटैच हैं। इन्हीं की तरह एक सहायक शिक्षिका भी हैं, जिनकी पदस्थापना तो सिंहपुर में है, पर वे अपनी सेवाएं इन दिनों कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा में दे रही हैं।

रद्दी की टोकरी में संचालनालय के आदेश

गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों का संलग्नीकरण/आसंजन समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में पदस्थ किए जाने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 30 मई 2017 एवं 21 जून 2019 को जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे सभी व्यक्तियों को मूल विभाग में पदस्थ किए जाने का निर्देश दिया गया था जिसके बावजूद कई विभागों में अब भी अटैचमेंट का खेल जारी रहने को गंभीरता से लेते हुए संचालक लोक शिक्षण ने सभी से अटैचमेंट समाप्त कर कर्मचारियों को

विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन

स्टार समाचार सीधी

महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र नेता शिवम शुक्ला के मार्गदर्शन में जितेंद्र सिंह परिहार और आशीष चौबे के सह नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्रों ने संजय गांधी महाविद्यालय ग्राउंड से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपर कलेक्टर को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिसमें महाविद्यालय में पढ़ने वाले एसटीएससी ओबीसी छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता 2 साल से स्वीकृत नहीं किया गया है। एसटीएससी ओबीसी छात्रावास चालू कराया जाय। महाविद्यालय सामान्य छात्रावास का भवन बनकर तैयार है परंतु अभी तक संचालित नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को 75 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर लैपटॉप एवं स्कूटी देने का वचन पत्र दिया गया था किन्तु दो सत्रों के बीच जाने के बाद भी छात्रों को नहीं मिल पाया यहां तक कि छात्रों को जो स्मार्टफोन प्रदान किया जाता था। अब वह भी नहीं दिया जा रहा है। संजय गांधी और कन्वा महाविद्यालय के बीच आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहां पर रेलिंग चौराहा बनवाया जाए। जिले में महिला एनसीसी इकाई चालू करवायी जाए सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत प्रतिशत आरक्षण प्राप्त छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। बस वाले छात्रों से दोगुना किराया वसूल रहे हैं, छात्रों की किराया सूची निर्धारित की जाए। जिससे छात्रों में काफी नाराजगी व्यक्त की गई है। छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर मांग की है कि महाविद्यालय स्तर की समस्याओं को सात दिवस के अंदर निदान करने का आश्वासन दिया गया है।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से छात्र नेता शिवम शुक्ला, जितेंद्र सिंह परिहार, आशीष चौबे, शिवानंद गुप्ता, रोशन द्विवेदी, आत्मा पांडे, राजलाल साकेत, रामचरण प्रजापति, देवेंद्र मौर्य, शिवम श्रीवास्तव, विराज गहरवार, सुनील साकेत, नव कुमार रजक, मृगेश जायसवाल, आकृति तिवारी, आरती कुशवाहा, मधु केवट, सुप्रिया मिश्रा, अनुराधा कोल, प्रीति साकेत, राजेश्वरी पनिका सहित हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

फीस वसूली : अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बेगमगंज निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से ट्यूशन फीस वसूली के विरोध में विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के पालकों ने बालक हायर सेकेंडरी ग्राउंड में एकत्रित होकर प्राइवेट स्कूल की मनमानी ट्यूशन फीस वसूली को रोकने के लिए नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अभिषेक चौरसिया को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों की मनमानी से निजात दिलाने की मांग की है।

पालको का कहना है निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से ट्यूशन फीस वसूली की जा रही है जबकि कोरोना वायरस फैलने के बाद लॉक डाउन के समय संपूर्ण भारत में करीब 5 माह स्कूल बंद रहे थे कुछ संस्थाओं ने व्हाट्सएप के माध्यम से आखिर के दो.तीन माह पढ़ाई कराई थी ऑनलाइन किसी भी संस्थान ने पढ़ाई नहीं कराई है। अब जबकि वार्षिक परीक्षा का समय करीब आ गया तो निजी स्कूल संचालकों द्वारा पूरे वर्ष की ट्यूशन फीस तो कुछ संस्थाओं द्वारा एडमिशन फीस की भी मांग की जा रही है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि लॉकडाउन के प्रथम 4 माह व पिछले वर्ष ली गई अप्रैल.मई 2 माह की ली गई फीस मार्च से लॉक डाउन प्रारंभ होने की वजह से कम की जाएए निजी स्कूल संस्थानों द्वारा शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए साथ पिछले सत्र की ट्यूशन फीस से वर्तमान ट्यूशन फीस का मिलान भी सुनिश्चित किया जाए ताकि गरीब मध्यम परिवार के आर्थिक स्थिति लॉक डाउन की वजह से जर्जर हो गई है उसके हिसाब से पालक अपने बच्चों की फीस जमा कर सकें। और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में होने से बचा सकें। यदि 1 सप्ताह के अंदर पालको की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आगामी मंगलवार की जनसुनवाई में पालक गांव उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।।

उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका था जब विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर आम पब्लिक के साथ जो कि सभी पालक हैं ज्ञापन देने पहुंचे। जिसमें प्रमुख रूप से राजेंद्र सोलंकी एडवोकेट, वजीर खान एडवोकेट, राजेश यादव एडवोकेट, संदीप विश्वकर्मा,कमल साहू, बसंत शर्मा, उपेंद्र ठाकुर, ओमकार यादव, संदीप लोधी, नासिर नवाब, नवल किशोर बबलू यादव, आरएन रावत एडवोकेट, सुखबीर सिंह ठाकुरए

कमल नामदेव,विक्रम सिंह ठाकुर, जफर शाह, एके खरे एडवोकेट, सगीर अली, राजू नेमा, प्रकाश राजपूत, डॉ रवि शर्मा, दिनेश पाटकर, संजीव सोनी, निक्की जैन सहित दर्जनों पालकगण शामिल थे।

एसडीएम अभिषेक चौरसिया एवं तहसीलदार एनएस परमार नायब तहसीलदार आनंद जैन ने पालकों की समस्या को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया की सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से चर्चा करने के बाद समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा।

छतरपुर (आरएनएन)। अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर बुधवार को एक समीक्षा बैठक स्थानीय हायर सेकेण्डरी क्रमांक 2 में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के सभी प्राचार्य एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

आप सभी अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर निवास कर कक्षा 10वीं की अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं, तभी परीक्षा परिणाम में सुधार होगा। यदि आपने ऐसा नहीं तो आप पर कार्यवाही होना तय है। यह बात जिला शिक्षा अधिकारी एसके शर्मा ने सभी प्राचार्यों से कही। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देश दिए कि वे सभी विषय शिक्षकों से इस तरह शिक्षण कार्य ले कि ई और डी ग्रेड के बच्चे सी ग्रेड या उससे उच्च ग्रेड हासिल कर सकें। निदानात्मक कक्षाओं में सिर्फई और डी ग्रेड प्राप्त बच्चों को ही प्रवेश दें।

श्री शर्मा ने अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम विश्लेषण को लेकर सभी प्राचार्यों से फेस-टू-फेस चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब आपका अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम ही लक्ष्य को नहीं छू पाया है तो वार्षिक परीक्षा परिणाम उतना कैसे आएंगा।

खराब अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम देने वाले लगभग 140 प्राचार्यों के विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई। सहायक संचालक शिक्षा जेएन चतुर्वेदी ने छात्रवृत्ति अपडेशन पर विस्तृत चर्चा की। एपीसी रामहित व्यास ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

विज्ञान सप्ताह दिवस का हुआ शुभारंभ बच्चों ने बनाई विज्ञान विषय पर पेंटिंग

पृथ्वीपुर ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर के शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान सप्ताह का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें छात्रों ने पोस्टर माडल प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक पेंटिंग कर अपना हुनर दिखाया। शासकीय महाविद्यालय में मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान सप्ताह के उपलक्ष्य में छात्रों की पोस्टर माडल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 35 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर विज्ञान के विभिन्न विषयों पर आकर्षक एवं ज्ञान वर्धक पोस्टरों का प्रदर्शन किया।

कार्यकम के मुख्य अतिथि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तरूण जैन एवं विशिष्ठ अतिथि तहसीलदार अनिल तलैया उपस्थित रहे। जिन्होंने माडल और पोस्टर के प्रदर्शन को बारिकी से निरीक्षण किया और मूल्यांकन उपरांत तरूण जैन ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उत्साहित किया। तहसीलदार अनिल तलैया ने कहा कि छात्र छात्राओं को इस प्रकार की प्रतियोगिता में लगातार भाग लेना चाहिये, जिससे उन्हे अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डा. डीएस यादव ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आकांक्षा विश्वकर्मा बीएएसी द्वितीय वर्ष, अंजली जोशी बीएससी का द्वितीय स्थान, मीनू साहू बीएससी द्वितीय वर्ष का तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रमाणपत्र और पुरस्कार तथा सभी भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये। क्रियान्वयन कमेटी में डा. सुप्रिया दीक्षित, डा. आरती शर्मा, डा. अनिल तिवारी शामिल रहे। साथ ही महाविद्यालय के डा. पदम नारायण, डा. रामराज उपाध्याय, सिद्वार्थ श्रीनेत, चंद्रजीत यादव, लाखन सिंह, रामधारी पाण्डेय, अमित कुमार पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह आर्य आदि लोग उपस्थित रहे।

राज्य शिक्षक संघ एवं पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित

खिरकिया (आरएनएन)। राज्य शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन खिरकिया में किया गया जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी विभाग के नवीन पेंशन धारक जो 2005 के बाद कि नियुक्ति है के कर्मचारियों का आकलन किया जाए अन्य विभाग के एनपीएस धारकों को संघ से जोड़ा जाए राज्य शिक्षक संघ की सदस्यता हेतु सभी को इससे जोड़ा जाए एवं संकुल बार साथियों को इसकी जवाबदारी दी जाए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक जागृति अभियान चलाया चलाया जाए एवं सभी विभागों के कर्मचारियों को दायित्व देते हैं जन अभियान के रूप में इसे बनाया जाए एवं सभी सदस्यों से राज्य शिक्षक संघ की सदस्यता ग्रहण करने हेतु अपील की गई इस अवसर पर बसंत शर्मा संतोष कुमार मालवीय एवं राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रदीप रिछारिया जिला अध्यक्ष महेश तिवारी उमेश सिटोके जीपी विश्वकर्मा के अलावा देवीदयाल सिंगोरे पुरुषोत्तम चौहान देवेश शुक्ला मंगेश राजवेद्य समीद खान उमेश नामदेव पल्लव सिंह ठाकुर सखाराम मोहे श्रीमती कनक रिछारिया श्रीमती मंजूषा आँजने साधना मिश्रा, संजीव साहू जी पी सिरशाम सहित आदि लोग उपस्थित थे सभी ने सदस्यता में शामिल होकर अपनी सहभागिता की ।

स्कूलों में बन रहे प्याऊ में व्यापक अनियमितताएं

– गोहनादेह में जीआई पाइप से जुड़ी प्लास्टिक पाइप लाइन

सिटियागोहना में हेडपंप के बाजू से बिछाया गई पाईप लाईन

सोहागपुर । बच्चों को स्कूलों में साफ स्वच्छ जल पिलाने के नाम पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचारी रूपी गंदगी फैलाई जा रही है। स्कूलों में प्याऊ का निर्माण किया जा रहा है जिनमें खुलेआम व्यापक स्तर पर अनियमिततायें करते हुये शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। कागजों में कहने को तो एजेंसी ग्राम पंचायत है, लेकिन अधिकांश सरपंच और सचिव इन निर्माण कार्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। सारा निर्माण वे ठेकेदार कर रहे जो जनपद से संबंधित अधिकारियों खास हैं। बहुत ही व्यापक कागजी हेराफेरी कर रिश्तेदारों को उपकृत करने स्वयं को लाभांवित करने का मेनेमेंट जमाया गया। सरपंच और सचिवों के डोंगल तो पहले से ही जनपद में हैं इसलिये बिल वाऊचर भी अधिकारियों की मनमर्जी के लग रहे हैं।

समूची रचना बीते माहों में पंचायत के खातों में आयी 15वे वित्त की राशि को हड़पने की है। योजनाबद्ध ढंग से आनन फानन 72 ग्रामों के स्कूलों में प्याऊ बनाने के लिये एएस और टीएस करा ली गयी है तथा करीब दस प्याऊ का निर्माण और प्लास्टिक की पानी की टंकी रखने तथा पाईप लाईन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष अन्य स्कूलों में यह कवायद तेजी से जारी है। जब इस संदर्भ में सीईओ श्रीराम सोनी से चर्चा की गयी तो उन्होंने बताया कि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्कूलों में उक्त कार्य के लिए एएस और टीएस करवायी गयी है । 15वें वित्त की राशि के एक हिस्से से इस तरह के कार्य करने के लिए पत्र के माध्यम से निद्रेश प्राप्त हुये थे। जब इन निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति देखी गयी तो मौके पर हालात बेहद ही अजीबोगरीब नजर आये तथा अनियमिततायें भी व्यापक स्तर पर देखनी को मिलीं। माध्यमिक शाला गोनहादेह माल में स्कूल की छत पर 1000 लीटर लिखी पानी की टंकी रखी गयी है। जिससे दो लोहे के पाईप लगभग इंच वृत्त वाले दीवार के छोर तक उतरे हुये हैं। इसके बाद इसमें प्लास्टिक की पाईप लाईन डालकर उसे जोड़ा गया है यह पाईप लाईन हेडपंप तक डाली गयी है।

जनपद की तकनीकी शाखा के सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक गड़बड़ी यहीं की गयी है टीएस में पूरी पाईप लाईन लोहे वाली ही डाली जानी चाहिये लेकिन दिखाने के लिये छोटे टुकड़े टंकी से लेकर दीवार तक ही लोहे के पाईप के रूप में डाले गये हैं बाकी अंडरग्राऊंड पाईप लाईन प्लास्टिक की ओर पतली डाली जा रही है इससे चंद दिनों बाद यह पूरी व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। यही हाल सिटियागोहना स्कूल में भी देखने को मिले हेडपंप तक प्लास्टिक का पाईप था तो दीवार पर दो पाईप लोहे के लगाए गए हैं।

इनका कहना है

पूरा पाईप ही जीआई पाइप लगना है और मैं जहां भी देखकर आया हूं, सभी जगह जीआई पाईप लगा है।

एचपी बिल्थरे,

एई मनरेगा जनपद पंचायत सोहागपुर

पीजी कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस की फीस कम करने की मांग

अभाविप के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने सौंपा प्राचार्य को ज्ञापन

झाबुआ ■ राज न्यूज नेटवर्क

शासकीय शहीद चन्द्रषेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में अध्ययनरत कम्प्यूटर साइंस के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के करीब 250 छात्र-छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जिला संयोजक कापंसिंह भूरिया के नेतृत्व में संस्था प्राचार्य एचआर अनिजवाल को ज्ञापन सौंपकर उक्त संकाय की फीस कम करने की मांग की है।

कॉलेज के उक्त संकाय के छात्र-छात्रा भावेश गवली, अजय, संदीप नायक, प्रकाश, धमेन्द्र, सुनील, रमेश, नेहा, पूजा, निर्मला, रंतू, मीत, सुमित आदि ने पीजी कॉलेज प्राचार्य श्री अनिजवाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सभी छात्र-छात्राएं बीएससी कम्प्यूटर साइंस के विद्यार्थी होकर जनभागीदारी समिति द्वारा 6 हजार 90 रू. फीस भरना सूचित किया गया है।

जिसमें एसटी-एससी के छात्र-छात्राओं के लिए 3 हजार 90 रू. है।

आंदोलन की दी चेतावनी

वर्तमान में कोरोना कालखंड में कक्षाएं नहीं लगी है। लेब कार्य भी नही हुआ है तथा वर्तमान में कॉलेज प्रबंधन के पास कम्प्यूटर विषय के प्राध्यापक भी नहीं है, जो छात्र-छात्राओं कोर्स कंपलीट करवा सके।

बावजूद इसके उक्त संकाय के समस्त विद्यार्थियों से पूरी फीस ली जाना सहीं नहीं है।

जिसे देखते हुए सभी विद्यार्थियों ने उक्त संकाय के तीनों सत्रों के छात्र-छात्राओं की फीस कम करने की मांग की है। साथ ही समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

कार्रवाई का दिया आश्वासन

ज्ञापन बाद उचित कार्रवाई हेतु संस्था प्राचार्य ने आष्वास्त किया। ज्ञापन की प्रतिलिपि छात्र-छात्राओं ने डीएवीवी इंदौर के कुलपति, जिला कलेक्टर एवं एसडीएम झाबुआ को भी कार्रवाई हेतु प्रेषित की है।

छात्राओं ने लिया स्वमूल्यांकन परीक्षा में हिस्सा

बड़वानी, (आरएनएन)। शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 8 फरवरी से से बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजनांतर्गत प्रशासन अकादमी भोपाल से प्रतिदिन 2 घंटे का स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से दिया जा रहा है। जिसमें अनिवार्य विषय एवं ऐच्छिक विषय के तहत 50 घंटों का प्रशिक्षण जारी है। यह ऐच्छिक विषय आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के तहत व्यवहारगत

कौशल, संगणक कौशल, उद्यमिता कौशल, कुक्कुट पालन, मस्त्य पालन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन प्रबंधन इत्यादि विषयों पर दिया जा रहा है।डॉ कविता भदौरिया ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 84 छात्राओं द्वारा स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण लिया जा रहा है। शासन की मंशा छात्र-छात्राओं को निकट भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराकर आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में आगे बढ़ना है। शासन द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण से सम्बंधित फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं बुधवार को 84 छात्राओं ने अल्पावधि रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वमूल्यांकन परीक्षा में भी हिस्सा लिया।

कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को ही मिलेगी छात्रावासों में रहने की अनुमति

खरगोन। प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त सीनियर महाविद्यालयीन छात्रावास विशिष्ट संस्थान इनमें आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय व गुरूकुलम विद्यालयों को खोले जाना है।

इसको लेकर आदिवासी विभाग के आयुक्त ने प्रदेश के जिला कलेक्टर्स को 22 फरवरी से छात्रावास प्रारंभ करने के निर्देश जारी कर दिए है। निर्देशों में कहा गया है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में केवल कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को ही रहने की अनुमति दी जाएं। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को छात्रावासों में नहीं रखा जाए। ऐसा करने से छात्रावासों में फिजिकल दूरी का पालन किया जा सकेगा। प्रदेश में विभाग के महाविद्यालयीन छात्रावासों को भी खोले जाने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को छात्रावासों में रखने के लिए अभिभावकों से अनिवार्य रूप से सहमित पत्र लेने को कहा गया है। प्रत्येक छात्रावास में अलग से एक क्वारेंटाईन कक्ष बनाया जाए।

छात्रावास अधीक्षक व अधीक्षकाओं का प्रशिक्षण कराने के भी निर्देश: आयुक्त ने जारी निर्देशों में यह भी कहा कि कोविड.19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षकाओं का प्रशिक्षण कराएं जाने व्यवस्था की जाएं। प्रत्येक छात्रावास को उनके निकटतम प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ केंद्र एवं अन्य शासकीय चिकित्सालयों के साथ समन्वय करते हुए वहां के चिकित्सकों के मोबाईल नंबर छात्रावास के सूचना पटल पर लिखा जाएं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से छात्रावासों में नियमित एवं साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएं। किसी विद्यार्थी की कोविड.19 के प्रारंभिक लक्षण या अन्य कोई समस्या होने पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाने की व्यवस्था हो।

छात्राओं की वास्तविक क्षमता पता लगाने के लिये काउंसलिंग जरूरी : डॉ. अग्रवाल

मन्दसौर। दशपुर इनरव्हील क्लब द्वारा मंडल 304 डिस्ट्रिक्ट चेयरमेन श्रीमती शशि गुप्ता की प्रेरणा से 10वी क्लास की छात्राओं के लिए कैरियर ओरियंटेशन पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें प्रमुख वक्ता डाइट कॉलेज प्रोफेसर डॉ. अलका अग्रवाल ने छात्राओं को मार्गदर्शन दिया।

बालिका शिक्षा पर 6 शोध कार्य करने वाली प्रोफेसर डॉ. अग्रवाल ने छात्राओं की काउंसलिंग कर उन्हें केरियर ओरियंटेशन के बारे में जानकारी दी। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि छात्राओं की वास्तविक क्षमता पता लगाने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। कुछ छात्र तो अपने करियर का ऑप्शन सही चुन लेते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं, जो कन्फ्यूज रहते हैं ऐसे में इस तरह के सेमीनार उनकी मदद करते है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि हाईस्कूल के बाद छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए किस-किस फील्ड में आगे बढ़ सकती है वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस विषय का चुनाव करें आदि महत्वपूर्ण बातें छात्राओं को बताई गई।

सेमीनार में क्लब अध्यक्ष शिल्पा मित्तल ने कहा कि कैरियर किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी भी इंसान की जीवनशैली का नेतृत्व करता है जिससे समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है। क्लब द्वारा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ के ऊपर एक निबंध प्रतियोगिता भी रखी गई जिसमें लगभग 40 छात्राओं ने भाग लिया जिसमें से प्रथम द्वितीय व तृतीय को क्लब द्वारा पुरस्कृत किया गया।

कुर्की की गई जमीनों से दुकानों में तोड़फोड़

शहडोल। बुढ़ार रोड स्थित श्रीजी मार्केट की तीन दुकानों को एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा ने कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके तहत नगर पालिका और पुलिस बल द्वारा दुकानों को सील करके अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया था, लेकिन दुकान मालिक विट्ठल सक्सेना ने उन दुकानों में तोड़ फोड़ कर दी है, जिसे न्यायालय की अवहेलना हो रही है, इसके बाद भी नगर पालिका और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, यह शिकायत नगर पालिका को अवगत करा दी गई है कि श्रीजी मार्केट के संचालक द्वारा सरकारी जमीन में 3 मंजिला इमारत खड़ी की गई है, उसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानें लाखों में बेची गई है। जिनकी नगरपालिका से मंजूरी भी नहीं है, इसके बाद भी तीन दुकानों को ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है, इन दुकानों को सील किए अभी महीना नहीं हुआ है, लेकिन श्रीजी मार्केट के संचालक दुकानों से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है।

आडिट के बहाने स्कूलों से जेबे भर रहे जिम्मेदार

शहडोल ■ राज न्यूज नेटवर्क

शासकीय स्कूलों में शासन द्वारा विभिन्न मदों से पूरे वर्ष भेजी जाने वाली राशि और उसके खर्च का ब्यौरा ऑडिटर की मोहर लगने के बाद आगे बढ़ जाता है। शासकीय स्कूलों सहित अन्य शासकीय विभागों में शासन के द्वारा भेजे जाने वाले मदों का क्या हाल होता है, यह किसी से छुपा नहीं है। ऑडिट के बहाने पहले से तय ओके रिपोर्ट के फेर में ऑडिटर भी इस हमाम में डुबकी लगाने से नहीं चूक रहे हैं।

सीएसी व बीआरसी बने केन्द्र

जिले के बुढ़ार स्थित जनपद शिक्षा केन्द्र के मुखिया सी.बी.शुक्ला सैकड़ों विद्यालयों व ऑडिटरों के बीच का केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं, विभिन्न संकुलों में बंटे जनपद क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत सीएसी अपने-अपने संकुल में स्थित माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं से दस्तावेज और शिक्षकों से 500 रूपये प्राथमिक व 1000 रूपये माध्यमिक शाला के हिसाब से राशि वसूल रहे हैं, यह राशि बीआरसी तक पहुंचाने का जिम्मा सीएसी को दिया गया है, जो ऑडिटर तक कुछ हिस्सा और दस्तावेज ओके कराने का कार्य सम्हाले हुए हैं।

सभी जनपद क्षेत्रों का यही हाल

बुढ़ार ही नहीं बल्कि जिले की अन्य सभी जनपदों का कमोवेश यही हाल है, मुख्यालयों में स्थित जनपद शिक्षा केन्द्र में पदस्थ बीआरसीसी, सीएसी के माध्यम से विद्यालयों से राशि वसूल रहे हैं और नीचे से ऊपर तक यह रकम पहुंच रही है, इनमें कुछ हिस्सा ऑडिटरों को और बाकी जिम्मेदारों की जेब में जाने की चर्चा है।

इनका कहना है....

अभी कोई ऑडिट नहीं हुए हैं और जो आप बात कर रहे हैं, उसकी मैं कोई बात नहीं करना चाहता।

सीबी शुक्ला ,समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र ,बुढ़ार

तराना मेले को लेकर हुआ मंथन

तराना (आरएनएन)। नगर परिषद क्षेत्र में वार्षिक मेले में दुकान व झूले लगाने की अनुमति दिए जाने के संबंध में पुछे जाने पर तराना एसडीएम ने कहा कि सभी दुकान संचालक मेले में दुकान लगाने की अनुमति और मेले की अनुमति उज्जेन कलेक्टर में बैठक होने के बाद निर्णय ले पाएंगे लेकिन किसी भी दुकानदार को इसके लिए तराना राजस्व की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। मेरे द्वारा अभी किसी भी प्रकार का लेटर या जानकारी ओर अनुमति नहीं दी गई है पर जो शासन-प्रशासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने बाबा तिलभांडेश्वर मंदिर के महंत ओर समिति के लोगों को बुलाया है इसके बाद निर्णय ले पाएंगे।

नागरिकों का व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए। बाहर से जब श्रृद्धालु एवं यात्रीगण हमारे शहर में आए तो शहर की स्वच्छता की प्रशंसा करें। आपने कहा कि प्लास्टिक पॉलिथीन के स्थान पर पेपर बेग अथवा कपड़े के बेग का उपयोग किया जाए। होटल/रेस्टोरेंट से निकलने वाले कचरे का निष्पादन स्वयं करें। डिस्पोजल का उपयोग कम करें। कचरा संग्रहण हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का भुगतान करें। होटल रेस्टोरेन्ट में स्वच्छता संबंधित साईनेज लगावे। हम स्वयं अपने घर, प्रतिष्ठान पर श्रमदान कर सफाई करें। होटल परिसर में शौचालय की उपलब्धता रखे। प्रतिष्ठान के सेप्टिक टेंक 3 वर्ष में खाली करवाये। रेस्टोरेन्ट एवं मिठाई दुकानों से पृथक-पृथक कचरा ही कचरा वाहनो को देवे। दुकान, होटल, प्रतिष्ठान के आस-पास नालियों मे कचरा ना डाला जावे। ग्राहकों से भी गंदगी ना करने, कचरा कुडेदान में डालने की अपील करें। कचरा केवल डोर टू डोर वाहनो में ही देवे। सडकों पर अतिक्रमण ना करे, चिन्हित स्थानों पर ही ठेला लगाये। शौचालयों/यूरिनल का प्रयोग करें। जल स्त्रोतो एवं नालों में कचरा ना डाले ऐसा करने वालो को रोके।

स्कूल की छत पर दबंगों का कब्जा

तराना (आरएनएन)। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों की बात आती है तो तालाब, चारागाह, चकरोड पर तो सभी की नजर जाती है लेकिन सरकारी स्कूलों की जमीनों पर कब्जों को प्रशासन भी खास तवज्जो नहीं देता। अब नई सरकार में शुरू किए गए एंटी भू-माफिया आपरेशन में सरकारी स्कूलों की जमीनों पर भी फोकस है। यही वजह है कि प्रशासन द्वारा ऐसे स्कूलों को चिन्हित कराया जा रहा है।

जहां सरकारी स्कूलों की जमीन दबंगों या गांव के लोगों के कब्जे में है। तहसील में कई सरकारी भूमि की बात की जाए तो हर ओर अवैध कब्जे में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वर्तमान में कुछ शासकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या है भी। तराना तहसील में 200 प्राथमिक और 100 माध्यमिक, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और शासकीय कालेज और अनुदान कॉलेज हैं। इन स्कूलों की स्थिति यह है कि उनके निर्माण के लिए या तो ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई या फिर गांव के जागरुक लोगों ने शिक्षा की जरूरत समझते हुए भूमि दान की। चूंकि तहसील के कई शासकीय स्कूल तीन दशक पहले के हैं इस कारण स्कूलों के पास अपनी काफी जमीन हुआ करती थी। धीरे-धीरे न तो विभाग ने अपने स्कूलों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम उठाया और वहां के शिक्षक भी किसी से बुराई.भलाई न लेने के कारण दबंगों के हौसले बढ़ते

गये। यही वजह है कि हर तराना तहसील के कई गांव में स्कूलों की जमीन पर कहीं दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया। तो वहीं आसपास के खेत वालों ने खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। कई बार स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने विभागीय तथा प्रशासनिक स्तर पर भी शिकायतें की हैंए लेकिन दबंगों के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप से उनकी एक न चली। धीरे-धीरे शिक्षकों ने भी विरोध लेना बंद कर दिया। अब जब एंटी भू.माफिया अभियान शुरू हुआ है तो विभाग ने भी गंभीरता दिखाई है। निर्धारित प्रारूप पर जहां माध्यमिक स्कूलों से अवैध कब्जों और अतिक्रमण का ब्यौरा मांगा गया है वहीं बेसिक शिक्षा के स्कूलों के लिए भी जिम्मेदारों को अवैध कब्जे चिन्हित कराकर रिपोर्ट मांगी गई थी। अब बात की जाय तो कार्रवाई तो भले ही बाद में होए लेकिन चुनौती इस बात को लेकर है कि क्या वाकई सही रूप से स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जे चिन्हित हो पाएंगे। काम तो अब राजस्व विभाग को करना है, क्योकि खसरा, खतौनी और नक्शों में दर्ज स्कूलों उर्फ कॉलेज की जमीन का मौके पर पहुंचकर मिलान कर सकते है। हालांकि अभी विभाग को रिपोर्टों का इंतजार है। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताते हुए कहां है कि 10 स्कूलों का अतिक्रमण का मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। जब आज सुबह राजस्व अनुविभागीय अधिकारी तराना एकता जयसवाल मौका मुआयना कर के कुछ स्कूलों में पहुंची तो उनकी आंख देखकर दंग रह गई होगी । मामला कुछ इस प्रकार है, तराना नगर से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव कमलीखेड़ा के शासकीय स्कूल के आस-पास की जमीन पर तो कुछ लोगों ने अपना आवास ही बना लिया है। वहीं गांव देवी खेड़ा में स्थित स्कूल में भवन निर्माण के समय से ही छत पर दबंगों का लगातार कब्जा बना हुआ है।

इनका ही कहना है...

जब इस विषय में बीआरसी अधिकारी ईश्वर सिंह शर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मोटरसाइकिल पर हूं मैं सुबह आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगा जिसमें 8 से 10 स्कूल के नाम है।

607 में से 396 बच्चों ने दी कक्षा 9वीं में चयन के लिए परीक्षा

सुसनेर ■ राज न्यूज नेटवर्क

जवाहर नवोदय विद्यालय जिसको बेहद अनुशासित स्कूल माना जाता है। हर मा-बाप की एक उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा भी नवोदय विद्यालय में पढे,इसके लिए अभिभावक को जी तोड मेहनत करे उसे इस लायक बनाते है। वह नवोदय की चयन परीक्षा को अच्छे से पास कर ले, किन्तु जब नवोदय विद्यालय के जिम्मैदार ही लापरवाही बरतेंगे तो फिर बच्चे कैसे इस परीक्षा को पास करेंगे।

बुधवार को कक्षा 9 वीं की नवोदय चयन परीक्षा में नवोदय विद्यालय प्रशासन की लापरवाहीयों के चलते सुसनेर में बनाए गए तीन परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा में सम्मिलित होने आए बच्चो व उनके साथ अभिभावको को काफी परेशानियों का सामना करना पडा। विद्यालय प्रशासन के द्वारा सुबह साढ़े 9 बजे परीक्षा का समय प्रवेश पत्र पर दिया गया जबकि परीक्षा 11 बजे से शुरू हुई जिसके चलते भूख और प्यास से तड़पते

बच्चों व अभिभावक जो कि 30 से 50 किलोमीटर दूरी तय करके आए थे। उन्हें इस लापरवाही के कारण काफी परेशानीयो को सामना करना पड़ा।

बच्चों को दो बजे तक नहीं छोड़ा

इस परीक्षा के समाप्त होने का समय साढे 12 बजे कर दिया गया था किंतु बच्चो को 2 बजे तक नहीं छोडा गया। इधर अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने के लिए आए डोंगरगांव के प्रेमसिंह रोनगरा और रूपेश,करण,राहुल सहित कई अन्य अभिभावको ने नवोदय विद्यालय पर आरोप लगाते हुएं कहां की जब परीक्षा का समय बढा दिया गया है या फिर कुछ परिवर्तन किया गया था तो इसकी जानकारी अभिभावकों को देना चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं करते हुएं परीक्षा केन्द्रों के बाहर सीध-सीधे जानकारी चस्पा कर दी गई। इस वजह से बच्चों को बगैर कुछ खाये पीये ही परीक्षा में सम्मलित होना पडा। तो वहीं नवोदय के विद्यालय के प्राचार्य एसी निगम अपनी अपनी लापरवाही से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।बता दें कि सुसनेर में नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 वीं में चयन के लिए शासकीय कन्या स्कूल,संतोष कैथोलिक हाई स्कूल और उत्कृष्ट स्कूल को परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। किन्तु इन तीनों ही परीक्षा केन्द्रों पर बच्चों व अभिभावको को परेशान होना पडा। कूल 607 में से 396 परीक्षाओं ने परीक्षा दी तो वही 211 अनुपस्थित रहे।

इनका कहना है-

चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों की कोविड-19 के चलते थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके हाथों को सेनेटाइज करवाना था। इसलिए उन्है जल्दी बुलाया गया था। इसको लेकर शासन केआदेश देरी से प्राप्त होने के कारण अभिभावको तक इसकी सुचना नहीं हो पाई थी। किन्तु परीक्षा केन्द्रों को इसकी जानकारी दे दी गई थी। कुछ परीक्षा केन्द्रों पर लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार करवाया गया है।

एसी निगम प्राचार्य,नवोदय विद्यालय सुसनेर।

प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन : सीएम

दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों को गांव में ही दिलाया जाएगा रोजगार

भोपाल, (प्रसं)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से पांव पसार रहा है। इसके बाद से सरकार अलर्ट पर है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीसी के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इसमें सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के मजदूर मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, वे अन्य प्रदेश में न जाएं, उन्हें मनरेगा के अंतर्गत गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। सीएम श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराई जाए। लक्षण होने पर जांच कराएं।

(अंतिम पेज भी देखें)

इंदौर, भोपाल और जबलपुर में विशेष सावधानी बरतें

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा आदि जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने से वहां विशेष सावधानी रखी जाए। इंदौर में 139, भोपाल में 70, बैतूल में 15, जबलपुर में 14 और छिंदवाड़ा में नौ नए मामले मिले हैं। इंदौर की पॉजिटिविटी रेट 6.6 प्रतिशत और भोपाल की 4.5 प्रतिशत है।

मेले स्थगित

कोरोना केस बढ़ने पर पचमढ़ी, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि में लगने वाले मेले स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही, यहां सभी प्रकार की सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट, सिवनी, बैतूल आदि सीमावर्ती जिलों से मजदूर रोज महाराष्ट्र कार्य के लिए जाते हैं। मनरेगा में इन्हें गांव में कार्य दिलाए जाने के निर्देश दिए।

वन अमले पर हमले और काले हिरन के शिकार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल (विधिक सवांददाता)। विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत ने वन्य प्राणी काले हिरन, चीतल, सांभर व नीलगाय का शिकार कर वन अमले पर हमला करने के आरोप में पकड़े गए आरोपी सिराज की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रवृत्ति को होने से निरस्त कर दिया। मामले में वन विभाग की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने जमानत अर्जी निरस्त करने की अपील की थी । गौरतलब है कि भोपाल वनमंडल ने 4 फरवरी को काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। गाड़ी में फराज, उमर समेत 4 लोग और थे। गाड़ी में वन्य प्राणी काले हिरन, चीतल, सांभर व नीलगाय का मांस तथा दो बंदूकें भी रखी थी। वन अमले ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो आरोपी सरकारी वाहन में लाठी-डंडों से हमला कर, फायर करने की धमकी देकर मौके से भाग निकले। उसी दौरान आरोपियों के वाहन से करीब 10 किलो वन्यप्राणी का मांस गिर गया। इसके बाद आरोपी फराज के घर से करीब 80 किलो वन्य प्राणी का मांस बरामद किया गया। मामले में फरार आरोपी फराज के भाई सिराज को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से जमानत अर्जी निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया था।

शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में अध्यापकों ने सीखी तमिल कन्नड़ भाषा

भोपाल (आरएनएन)। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा में हमारा चिंतन निज हित में न होकर राष्ट्र हित में होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर कर युवा पीढ़ी को उसका लाभ दिलाया जाएगा। मंत्री श्री परमार राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड अंतर्गत सबके लिए शिक्षा ईएफए विद्यालय योजना की कार्यशाला के दौरान प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान भोपाल में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा पीढ़ी ही आत्म निर्भर भारत और आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के सपने को साकार करेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य मुक्त विद्यालय बोर्ड द्वारा सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें भाषा प्रयोगशाला, रीडिंग मैराथन और खुश स्कूल खुश शिक्षक विषय शामिल किए गए थे। कार्यशाला के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी समूहों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में विगत 4 माह से 200 अध्यापकों को तमिल भाषा तथा कन्नड़ भाषा का अध्यापन तथा बोलने का अभ्यास कराया गया। इस बहुभाषी पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों द्वारा तमिल तथा कन्नड़ भाषा में रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय बोर्ड के निदेशक प्रभात राज तिवारी ने मुक्त विद्यालय बोर्ड के माध्यम से स्थापित किए जा रहे विश्व स्तरीय 53 विद्यालयों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए।

कोरोना संकटकाल में पुस्तकें खरीदने को लेकर डरे हुए हैं अभिभावक

नवीन शिक्षण सत्र की तैयारी, फिर पालकों पर किताबें खरीदने का बोझ

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों से मांगी ई मेल पर किताबों की सूची

भोपाल (आरएनएन)। एक ओर कोरोना का संकट फिर से दहशत फैलाने की आहट दे रहा है वहीं दूसरी ओर नवीन शिक्षण सत्र की तैयारी हो रही है। इस बीच खासकर उन अभिभावकों का दर्द सामने आ रहा है, जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सभी स्कूलों से ई-मेल पर किताबों की सूची मांगी है।

इनका कहना है कि इन स्कूलों से बड़े विक्रेताओं के अर्से से बने संबंध अभिभावकों के लिए मुसीबत का कारण बने हैं। इन्हीं के कारण शासन के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। डीईओ कार्यालय ने सीबीएसई स्कूलों के संचालकों से पुस्तकों की सूची मंगाने की तैयारी की है।

बताना होगा कि अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होने की संभावना है। छोटे विक्रेताओं का आरोप है कि कुछ सीबीएसई स्कूल प्रायवेट पब्लिशर्स की किताबें सिर्फ कमीशन के लिए चलाते हैं। प्रायवेट पब्लिशर्स की किताबों को चलाने में पचास प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। यह कमीशन स्कूल प्रबंधन व बुक सेलर के पास जाता है। छोटे सेलरों का कहना है कि प्रायवेट पब्लिशर्स व स्कूल प्रबंधन की सीधे व्यवसायिक रिश्ते होते हैं। प्रायवेट पब्लिशर्स द्वारा स्कूल प्रबंधन को कमीशन देने के बाद उसकी किताबें विशेष दुकान पर बिकने के लिए पहुंचती है। विशेष दुकान से भी स्कूल प्रबंधन द्वारा कमीशन लिया जाता है। स्कूल प्रबंधन को दो जगहों से कमीशन मिलता है। कई प्रायवेट पब्लिशर्स पचास प्रतिशत तक कमीशन देते हैं। नतीजतन सीबीएसई स्कूल द्वारा एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाई जाती है। इसका खामियाजा सीधा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। बता दें कि पिछले साल इसी कमीशनखोरी से निपटने के लिए छोटे जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना के समक्ष पूरी समस्या अभिभावकों ने रखी थी।

मांग की गई थी कि सभी स्कूलों की सूची जमा कराई जाए ताकि सभी बुक सेलर सूची के आधार किताबें समय के साथ रख सके। साथ ही सूची जमा करने बाद बदलने वाले स्कूलों पर एनओसी निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इधर जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि राजपत्र में स्पष्ट प्रकाशन है कि स्कूल संचालक किताबों की सूची स्कूल के बाहर चस्पा करें। इसका पालन सभी को करना होगा। उन्होंने बताय कि हमने भी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वह सूची ई-मेल के माध्यम से कार्यालय में जमा कराएं।

दर्जन भर से ज्यादा प्रकाशक हावी

अभिभावकों का आरोप है कि राजधानी में एक दर्जन से अधिक पब्लिशर्स की किताबें निजी स्कूलों में ज्यादा चलाई जाती है। इसमें ऑक्सफोर्ड, ओरियंट ब्लैक स्वान, सफायर, पीयरसन, लांग मेन कोरोडोबा, आक्सफोर्ड तरूण, श्रजन, रचना सागर, विटानिका, कीप्स इंडिया, एसके, सरस्वती प्रकाशन, ट्रेसियन, नेक्स्ट एजुकेशन, एस चांद, भारती भवन, एवरग्रीन, होलीफेथ सहित अन्य शामिल है। वहीं कुछ सीबीएसई स्कूल प्री कक्षाओं में विभिन्न पब्लिशर्स की किताबों से मटेरियल लेकर खुद की किताब प्रिंट करवाते है। यह किताबें भी विशेष दुकानों पर मिलती है। इतना ही नहीं ट्रेसियन पब्लिशर्स में भोपाल डाइस के कई फादर व सिस्टर किताबों के लेखक हैं। यही किताबें मिशनरी स्कूलों में ज्यादा चलती हैं। बुक सेलर बुक्स एन बुक्स, महेश ट्रेडर्स जिसी, प्रियंका बुक्स डिपो मारवड़ी रोड, सुरेश स्टेशनरी बैरागढ़, स्नेह बुक सेंटर सहित अन्य शामिल है। अधिकांश छोटे बुक सेलर इन्हीं से बुक्स खरीदकर स्कूलों में सप्लाई करते है। इस संबंध में आर्च डायसिस आफ भोपाल के पीआरओ फादर मारिया स्टीफन ने कहा कि हम इस दिशा में गंभीर हैं। आर्च डायसिस से जुड़े स्कूलों को विशेष दुकानों से किताब को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके है। स्कूलों की किताबें सभी दुकानों पर होना चाहिए। प्रशासन जो तिथि तय करे उसके अनुसार सूची जमा करना चाहिए।

मंत्रालय से लेकर पीएचक्यू तक काम समान फिर भी विसंगति में फंसा वेतनमान

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

राज्य सेवाओं के अधीन एक ही प्रकार का काम करने वाले स्टेनोग्राफर यानि शीघ्रलेखकों के वेतनमानों में विसमता कर सरकार ने आपसी घमासान के हालात निर्मित कर दिए हैं। हर अफसर और मंत्रियों के यहां अपनी महती जवाबदारी निभाने वाले इन संवर्गीय सेवकों का आरोप है कि सरकार ने एक प्रकार से लड़ाने का कार्य किया है। क्योंकि मंत्रालय सेवा के अलावा विधि और पुलिस विभाग का एक सुनियोजित तरीके से वेतनमान बढ़ाया गया है।

स्टेनोग्राफरों का दर्द है कि समस्त विभागों में राज्य सेवाओं के शीघ्रलेखक और पदोन्नत पद की न्यूनतम एवं अधिकतम वेतनवृद्धि की दरें पूर्व से ही निर्धारित हैं। शर्तों की समकक्षता और सापेक्षिता भी परस्पर रही है। राज्य सेवाओं में अनुसचिवालयीन शीघ्रलेखक श्रेणी की नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों को भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही निर्धारित किया गया है, लेकिन ग्रेड पे में विसमता रख दी गई है। मंत्रालय सेवा के अलावा पुलिस और विधि विभाग के शीघ्रलेखक 3600 ग्रेड-पे पा रहे हैं। जबकि प्रदेश के अन्य सभी विभागों में ग्रेड-पे 2800 रूपये हैं।

पुलिस विभाग में 23 जनवरी 2014 और विधि एवं विधायी कार्य विभाग में 21 जुलाई 2016 को आदेश जारी कर ग्रेड-पे निर्धारित किया गया था।

इधर अन्य विभागों में यह व्यवस्था नहीं होने से स्टेनोग्राफरों में आपसी द्वन्द शुरू हुआ है। स्टेनोग्राफरों का कहना है कि सेवा और मूल शर्त एक है, जबकि मूल वेतनमान में विसंगता रख दी गई है। न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन बैंड में भी बड़ा अंतर रख दिया गया है।

विवादित रहे लागू हुए वेतनमान

60 और 70 के दशक से अभी तक जो-जो वेतनमान प्रदेश में लागू हुए हैं, वह प्रारंभिक दौर से सवालों के घेरे में रहे हैं। सबसे पहले प्रदेश में ताराचंद वेतनमान लागू किया गया था। इसके बाद पांडेय वेतनमान आया। इन दोनों ही वेतनमानों में प्रदेश के सेवकों को बड़ी आर्थिक क्षति दी गई। इसके उपरांत चौधरी और फिर बोरा वेतनमान सरकार ने लागू किया। यह वेतनमान भी विवादों में रहे हैं। बोरा वेतनमान के समय से ही प्रदेश के शीघ्रलेखकों के वेतनमान और ग्रेड-पे में अंतर रख दिया गया।

बोले स्टेनोग्राफर...

काम समान है, लेकिन वेतनमानों में बड़ा अंतर है। सेवा शर्त और मूल वेतनमान एक है, लेकिन ग्रेड-पे में अंतर रख दिया गया है। इससे प्रदेश के एक हजार स्टेनोग्राफरों को मासिक 5 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है।

एमएस मेवाड़, प्रांताध्यक्ष, स्टेनोग्रार संघ, मप्र

हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि जब मंत्रालय, पुलिस और विधि में हुआ तो फिर अन्य विभागों में भी समान वेतनमान और ग्रेड-पे होना चाहिए। इस विसंगति से अन्य विभागों के स्टेनोग्राफरों में निराशा है। अब शीघ्र ही आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।

आलोक तिवारी, महामंत्री, स्टेनोग्राफर संघ मप्र

विद्यार्थियों के लिए करें यूनिफार्म डिजाइन, जीतें नगद पुरस्कार

भोपाल । प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म डिजाईन में बदलाव किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म डिजाईन के लिए प्रतियोगिता 5 फरवरी से प्रारंभ की गई है। यह प्रतियोगिता 25 फरवरी तक चलेगी। इच्छुक डिजाईनर 25 फरवरी तक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रविष्टियां भेजने के लिए गुरुवार को अंतिम तारीख है। प्रथम एवं द्वितीय उत्कृष्ट डिजाइन का होगा चयन प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका संवर्ग के लिए प्रथम एवं द्वितीय उत्कृष्ट डिजाइन का चयन किया जायेगा। प्रत्येक संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिभागी को क्रमशः एक लाख एवं 50 हजार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

युवाओं को प्रदेश में ही मिलेगा रोजगार

मंत्री भार्गव ने रोजगार के क्षेत्र में नवाचार करने के निर्देश

भोपाल। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के तहत रोजगार सृजन के लिये गठित रोजगार समूह तीन माह में रिपोर्ट तैयार करेगा।

उन्होंने कहा कि रोजगार गतिविधियों में वर्तमान संसाधनों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। मंत्री श्री भार्गव ने यह निर्देश आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप तैयार करने के लिये गठित अंतर्विभागीय रोजगार-समूह की बैठक में दिए। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य रोजगार संसाधनों की बढ़ोत्तरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार, स्व-रोजगार प्राप्त हो, इसके लिये सभी विभाग समन्वित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि रोजगार-समूह की आगामी बैठकों में विशेषज्ञ संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जाए। प्रदेश में आजीविका मिशन और ग्रामोद्योग इकाईयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

नीट पीजी के ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च तक

ग्वालियर। देशभर के मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमडी, एमएस या फिर अन्य मेडिकल पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एमबीई) इस प्रवेश परीक्षा को कराएगा। इसके लिए पंजीयन की शुरूआत मंगलवार से हो गई। ऑनलाइन पंजीयन 15 मार्च तक किए जा सकते हैं। इसके प्रवेश पत्र 12 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। यह प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। परिणाम की घोषणा 31 मई को होगी।

जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेला 27 को

ग्वालियर। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को साकार करने के लिये ग्वालियर जिले में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिला प्रशासन की पहल पर जिला रोजगार कार्यालय एवं अन्य विभागों के सहयोग से 27 फरवरी को जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेला लगाया जायेगा। इस दिन यह मेला यहाँ बिरला नगर स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रातः 10 बजे शुरू होगा।

युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सुव्यवस्थित ढंग से रोजगार मेला आयोजित कराने के लिये जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किशोर कान्याल को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। उप संचालक जिला रोजगार कार्यालय श्रीमती प्रियंका कुलश्रेष्ठ ने बताया कि रोजगार मेले में आठवीं, दसवीं व बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आईटीआई योग्यताधारी आवेदकों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी का मौका मिलेगा। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। निजी कंपनियों में नौकरी करने के इच्छुक आवेदकों से रोजगार मेले में शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ लेकर आने की अपील की गई है। रोजगार मेले में भाग लेने के लिये आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं। जिन नियोजकों एवं औद्योगिक संस्थानों को कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन की जरूरत है, उनसे भी कहा गया है कि वे 25 फरवरी तक अपनी सहमति रोजगार कार्यालय को अवश्य दे दें।

UPSC: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

लॉकडाउन में ओवरएज हुए छात्रों को अतिरिक्त मौका नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। यूपीएससी 2020 की परीक्षा देने के अंतिम मौके से चूकने वाले छात्रों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्रों की याचिका खारिज कर दी। दरअसल,यूपीएससी परीक्षा देने की जिन लोगों की उम्र सीमा पिछले साल अक्टूबर 2020 में खत्म हो गई थी, वह अंतिम प्रयास के समय को बढ़ाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने मौखिक रूप से सुझाव दिया था कि एक अतिरिक्त मौका इस स्थिति में दिया जा सकता है कि उम्मीदवार निर्धारित आयुसीमा पूरी न कर चुका हो। इससे पहले, 05 फरवरी को केंद्र ने फाइनल अटेम्प्ट खो चुके उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी आयु ऐज बार के भीतर ही हो। इसी मामले में छात्रों ने ऐज रिलेक्सेशन की भी मांग की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ओवरऐज छात्रों को रिलेक्सेशन दूसरे स्टूडेंट साथ अन्याय होगा

अदालत ने यह माना कि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी को पर्याप्त समय मिला है और यदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए ऐज रिलेक्सेशन दिया जाता है तो यह अन्य स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसके बाद आगे भी छात्र इस फैसले का हवाला देकर ऐज रिलेक्शन की मांग कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं निकलेगा। 25 जनवरी को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी थी कि ऐसे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका प्रदान नहीं किया जाएगा जिनके सभी अटेम्प्ट्स पूरे हो चुके हैं।

18 मार्च को होगी नीट पीजी की परीक्षा, डेट शीट जारी

भोपाल। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नोटिस जारी कर एमडी, एमएस पाठ्यक्रम के लिए आयोजित की जाने वाली नीट पीजी परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक नीट पीजी की परीक्षा 18 अप्रैल को अयोजित कर 31 मार्च तक परिणाम जारी किए जाएंगे। परीक्षा फार्म 23 फरवरी दोपहर 3 बजे से 15 मार्च 2021 तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। परीक्षा में अब 300 की जगह 200 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि मार्किंग स्कीम एवं समय अवधि (साढ़े तीन घंटे) में कोई बदलवा नहीं किया है।

विक्रम विश्वविद्यालय

यूनिवर्सिटी रोड, माधव भवन

विक्रम वाटिका के पास, उज्जैन- 456010 (म.प्र.)

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2021/350 **दिनांक : 17.02.2021**

पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा अधिसूचना-2021

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा आयोजित **पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा-2021** के आवेदन दिनांक 05.03.2021 तक एवं विलंब शुल्क के साथ **दिनांक 08.03.2021 तक** एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट **vikram.mponline.gov.in** के माध्यम से भरे जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी विक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.vikramuniv.ac.in** पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/99965/45233/2021

कुलसचिव

राजधानी में बढ़ेगी सख्ती, मेले और हाट में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राजधानी में जनवरी माह की शुरुआत से ही कोरोना केसों की संख्या कम होती जा रही थी। कई दिन केस की संख्या 30 से 40 के बीच रही। लापरवाही बढ़ने से ये संख्या फिर बढ़ने लगी है। कहीं ये आंकड़ा पहले की तरह न पहुंच जाए, इसलिए अभी से सख्ती बरतने को लेकर मंगलवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एसडीएम की अध्यक्षता में समाजसेवी और व्यापारियों की बैठक सर्किल स्तर पर की जाएगी। इसमें प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स में सोशल डिस्टेंस और मास्क के लिए लोगों को समझाइश देने के लिए कहा जाएगा। जिन मेलों, हाट को अनुमतियां जारी की गई हैं, उनमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अगर, कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो लोगों पर जुर्माने के साथ उक्त समिति, संस्था पर भी कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में दुकानदारों को मास्क लगाने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। सैनिटाइजर रखना होगा।

नई अनुमति नहीं

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। आगामी आदेश तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। मेलो के संबंध में पूर्व में जारी अनुमतियों के अलावा नई अनुमति नहीं देंगे।

अविनाश लवानिया,
कलेक्टर

IIT मुंबई व कैरियर कॉलेज का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेबिनार

भोपाल। कैरियर कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट द्वारा अभुदय 2.0 के अंतर्गत आईआईटी मुंबई के सहयोग से वेबिनार आयोजित किया गया। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा आईटी साक्षरता ज्ञान विषय पर आधारित इस वेबिनार में आईटी मुंबई से स्वप्निल मोरे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल इंडिया स्कूल एवं एनजीओ ट्रेनिंग हेड ने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस सॉफ्टवेयर में अलग-अलग तरह के कोर्सेज हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए यह सॉफ्टवेयर फ्री है, जिसका उपयोग कर विद्यार्थी आईटी के क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। इस वेबिनार में प्रदेश के लगभग 25 स्कूलों से संयोजकों ने भाग लिया।

1227 का चयन, 432 को मिले नियुक्ति पत्र

1656 बेरोजगारों ने प्लेसमेंट ड्राइव में कराया था पंजीयन

-निज प्रतिनिधि-

गुना। जिला पंचायत विश्राम गृह में बुधवार को युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने 12वां प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। जिसमें देश-प्रदेश की 13 कंपनियों एवं 3 प्रशिक्षण संस्थाईओं द्वारा 1227 बेरोजगार युवाओं का चयन किया गया। वहीं कंपनियों द्वारा 940 तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के लिए 288 चयनित युवा बेरोजगार शामिल है। आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में कंपनियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों में से 432 युवाओं को मौके पर ही नियोजकों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। इस प्लेसमेंट के लिए 1656 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया था।

प्लेसमेंट ड्राइव में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

हुनर है तो उसे तराशे : केपी

प्लेसमेंट ड्राइव के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हुनर है तो उसे तराशें। रोजगार के मिले अवसर का पूरा लाभ उठाएं और रोजगार पाएं। इससे उनके परिजनों को बहुत प्रसन्नता होगी। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार उनके साथ ही और हर तरह से स्वरोजगार को लेकर उनके लिए मदद उपलब्ध करा रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि वे केवल नौकरी ही नहीं ढूंढें बल्कि आत्मनिर्भर बनने स्वरोजगार की भी सोचें। स्वरोजगार के लिए सरकार की बहुत सारी हितग्राहीमूलक योजनाएं हैं। वे इससे स्वयं रोजगार पाएं और अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दें। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि वह अपने हुनर एवं व्यवहार से जिले का नाम रोशन करें।

जरूरत के हिसाब से कार्य करें युवा : पुरुषोत्तम

इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने कहा कि जिले के युवाओं में क्षमता और हुनर की कमी नहीं है। सरकार उन्हें रोजगार के अवसर के लिए प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करना चाहिए। इसके लिए शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन आगे बढ़ने प्रगति और आमदनी बढ़ने के रास्ते अनुभव से खुलते हैं। धीरे-धीरे आमदनी बढ़ने से वह बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को भी प्लेसमेंट ड्राइव में रोजगार के अवसर का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह अवसर को पहचानें और जो ऑफर मिले उससे अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें।

1600 को मिली नौकरी

प्लेमसमेंट ड्राइव के प्रारंभ में जिला रोजगार अधिकारी बीएस मीना ने बताया कि जिले में अब तक 11 प्लेसमेंट ड्राइव जिला एवं विकासखंड पर आयोजित किए गए हैं। इनमें 3314 युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित कर 1544 रोजगार के इच्छुक युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। जिसमें से 1600 से अधिक युवाओं द्वारा अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली गयी है। साथ ही जिले के 17 विभागों द्वारा शासन की विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनांतर्गत 14948 व्यक्तियों को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह सिकरवार, विकास जैन नखराली, सचिन शर्मा, रमेश मालवीय, जिपं सीईओ नीलेश पारीख आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अशीष टांटिया ने किया तथा आभार एसडीएम अंकिता जैन ने माना।

परीक्षा के लिए शिविर 26 से

-निज प्रतिनिधि-

गुना। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनसीसी इकाई डी कंपनी के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कैडेट्स के लिए सत्र 2020-21 अंतर्गत बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए विशेष सीएसीटी कैंप का आयोजन महाविद्यालय के मुखर्जी स्टेडियम में 26 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। 35 वीं बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल धीरेंद्र सिंह के अनुसार बी प्रमाण पत्र तीन दिन एवं सी प्रमाण पत्र के लिए पांच दिन का कैंप रहेगा। जो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगा। रात में कैडेट नहीं रुकेंगे। कैम्प में केवल उन्हीं कैडेटों को अनुमति दी जाएगी जिनके कैम्प फार्म पूर्ण रूप से भरे होंगे, वे निर्धारित वर्दी में रहेंगे। पीजी कॉलेज के प्राचार्य के डॉ बीके तिवारी ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कैडेट्स को अपने साथ मास्क, हैण्ड ग्लब्स एवं सेनेटाइजर आवश्यक रूप से लाना है। इस कैम्प में महाविद्यालय की एनसीसी इकाई के 84 कैडेट भागीदारी करेंगे। यह कैम्प सत्र 2020-21 का अंतिम शिविर है।

शीर्ष न्यायालय में याचिका खारिज

यूपीएससी परीक्षा: उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका

नई दिल्ली स्वससे।

शीर्ष न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी, जो अक्टूबर, 2020 में अपनी आयु सीमा के तहत अंतिम अवसर में कोरोना महामारी के कारण शामिल नहीं हो पाए थे और जिनका आखिरी अवसर भी बर्बाद हो गया।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय किया। मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई थी कि वह कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न व्यवधानों के कारण यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 में उपस्थित नहीं हो पाए। इसके बदले उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2021 के लिए अतिरिक्त प्रयास देने की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो अपने अंतिम प्रयास के रूप में सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स -2020 के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें विशेष रूप से सीएसई-2021 तक सीमित एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स -2021 में शामिल होने के लिए आयु सीमा से वर्जित न हों। लेकिन जिनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है, उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता। वहीं, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं का कहना था कि सिर्फ अतिरिक्त प्रयास देने से कोई लाभ नहीं है, उम्र समय सीमा में भी छूट प्रदान की जानी चाहिए।

उनका यह भी कहना था कि यह बहुत कठिन परीक्षा है, ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री व कोचिंग क्लास की जरूरत होती है। लेकिन कोविड-19 के कारण यह सब संभव नहीं हो सका। साथ ही कई परीक्षार्थी डॉक्टर, पुलिस आदि कोरोना योद्धा भी है, जो परीक्षा की तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर सके।

तकनीकी शिक्षा मंत्री सिंधिया ने की आईटीआई में समीक्षा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ पॉलीटेक्निक के बच्चों को भी मिले। इसके लिए नीति तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। सिंधिया बुधवार को गोविन्दपुरा आईटीआई में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की समीक्षा कर रही थी। मंत्री सिंधिया ने कहा कि छात्रवृत्ति सेल में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से अपने कर्त्तव्य को निभाएं। बच्चों से समन्वय स्थापित कर उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा भी की। मंत्री सिंधिया ने कहा कि बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित बच्चों का डाटा एनालिसिस कर एक सप्ताह में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

एमएमएमवीवाय के तहत पॉलीटेक्निक के छात्रों के लिए भी बनेगी नीति

छात्रवृत्ति सेल में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करें

पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ को कटने से बचाएं

तकनीकी शिक्षा मंत्री सिंधिया गोविंदपुरा स्थित आईटीआई पहुंचकर परिसर का निरीक्षण किया। परिसर में कटे पेड़ा देखकर उन्होंने आईटीआई के प्रचार्य पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह शिक्षण संस्थान है। यहां बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। सभी मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें और परिसर को स्वच्छ बनाये। उन्होंने पौधरोपण और उनकी सुरक्षा के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर संचालक रोजगार षणमुख प्रिया मिश्रा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीएसपी हरजिंदर सिंह उपस्थित थे।

मानसून के पूर्व सभी भवनों के प्लिंथ लेवल को करें पूरा

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नरेला संकरी स्थित निर्माणाधीन ग्लोबल स्किल पार्क की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून के पूर्व सभी भवनों के प्लिंथ लेवल का कार्य पूर्ण हो यह सुनिश्चित करें। सिंधिया ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे समय-सीमा में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सुदृढ़ करते हुए युवाओं, महिलाओं एवं समाज के अशक्त वर्गों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्भर बनाना है। इस अवसर पर मंत्री सिंधिया ने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। ग्लोबल स्किल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरजिंदर सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूली बच्चों को मिलेगी सेहत की शिक्षा, शिक्षक बनेंगे 'स्वास्थ्य दूत'

शुरू हुआ शिक्षकों का प्रशिक्षण, 25 मार्च को होगा समाप्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

स्कूल से कोरोना संक्रमण से बचाव सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान लेकर बच्चे घर और अपने आस-पास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 'स्वास्थ्य दूत' बनाया जा रहा है, जो विद्यार्थियों को बीमारियों से रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग अप्रैल से नए सत्र का शुभारंभ करने जा रहा है। अभी हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल चल रहे हैं। नए सत्र से पहली से आठवीं तक के स्कूलों को भी खोलने की योजना है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मप्र द्वारा स्कूलों में स्कूल हेल्थ कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों से 240-240 शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर चुना गया है। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 फरवरी से 25 मार्च तक छह चरणों में 11 मॉड्यूल में चलेगा। इसमें शिक्षकों को कोरोना से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरती जाएं और स्वच्छता का कैसे ध्यान रखा जाए, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।

11 विषय चिन्हित किए

स्कूली स्वास्थ्य में 11 विषय चिन्हित किए गए हैं। इनमें कोरोना संक्रमण से बचाव, स्वस्थ होना, भावनात्मक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य, अंतरव्यैक्तिक संबंध मूल्य, लैंगिक समानता, पोषण आहार, स्वस्थ और साफ-सफाई, स्वस्थ जीवनशैली का प्रोत्साहन, प्रजनन स्वास्थ्य सहित अन्य विषय शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति कर सकें जागरूक

स्कूलों के शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर चुना गया है, ताकि वे बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति खास तौर पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर सकें।

जयश्री कियावत, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय

कार्यक्रम के लिए प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षक चुने जाएंगे

'स्वास्थ्य दूत' कार्यक्रम में प्रत्येक सरकारी स्कूल में दो शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर के रूप में चुना जाएगा। इनका काम रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्रसारित करना होगा। खासतौर पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये बच्चों को जागरूक करेंगे। ये शिक्षक इस काम में कक्षा प्रतिनिधियों से भी सहयोग लेंगे, जो हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर संदेशवाहक कहे जाएंगे। ये कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे।

मोबीक्विक यूजर्स से वसूलेगा मेंटेनेंस चार्ज

नई दिल्ली। अगर आप भी देश के बड़े डिजिटल वॉलेट में से एक मोबिक्विक यूज करते हैं तो आपके लिए ये बुरी खबर है। दरअसल, भारत में पहली बार मोबिक्विक अपने इनएक्टिव यूजर्स से 100 रुपए से 140 रुपए के बीच वॉलेट मेंटेनेंस चार्ज वसूल करेगा।

टेक्नोलॉजी ने दिखाया ठेंगा, अब बगैर अँगूठा लगाए मिलेगा राशन

सर्वर फेल होने से बदली व्यवस्था, समग्र आईडी लाना जरूरी

नगर संवाददाता | जबलपुर

कई दिनों की लंबी मशक्कत के बाद राशन वितरण में तैयार हुए बायोमेट्रिक सिस्टम ने फिर ठेंगा दिखा दिया है। नतीजतन, जबलपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश में राशन वितरण की प्रक्रिया लड़खड़ा गई है। परेशानी को देखते हुए अब नए आदेश दिए गए हैं कि राशन हासिल करने के लिए अँगूठा नहीं लगाना होगा। इसके बदले समग्र आईडी के हिसाब से अनाज वितरण किया जा सकेगा।

राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण को लेकर हर दिन कोई न कोई विवाद होता है इसके चलते पिछले कुछ दिनों से तकनीकी समस्या होने के कारण राशन का वितरण दुकानों से नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन राशन वितरण में परेशानियाँ हो रही थीं। यह समस्या जबलपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश में हो रही थी।

सभी कलेक्टर्स को निर्देश | खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक ने सभी कलेक्टर्स को लिखे पत्र में कहा है कि वर्तमान में डाटा सेंटर में स्थापित सर्वर में तकनीकी समस्या आने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन से पात्र हितग्राहियों को सामग्री का वितरण नहीं हो पा रहा है। तकनीकी समस्या के निराकरण होने तक उचित मूल्य की दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीनों को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन कर दिया गया है।

ध्यान रहे गड़बड़ी न हो | खाद्य विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि हितग्राहियों को समय पर राशन प्रदान कराया जाए। राशन के लिए जरूरी है कि समग्र परिवार आईडी के आधार पर पीओएस मशीन से सामग्री का वितरण कराया जाए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पात्र हितग्राहियों को ही राशन मिले और गड़बड़ी की तनिक भी गुंजाइश न रहे।

कक्षा 10वीं और 12वीं की अभ्यास परीक्षाएँ 1 मार्च से

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर| जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की अभ्यास परीक्षाएँ 1 मार्च से कराने का आदेश जारी किया है। ये परीक्षाएँ जिला स्तर पर आयोजित की जाएँगी। गौरतलब है कि माशिमं की कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल परीक्षाएँ 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों व परीक्षाओं के बेहतर परिणाम लाने के लिए गत दिनों शिक्षकों के लिए उन्मुखी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। शिक्षा विभाग का लक्ष्य 90 प्रतिशत से अधिक परीक्षा परिणाम लाना है।

विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका की व्यवस्था स्थानीय परीक्षा मद से की जाएगी। मूल्यांकन जिला स्तर पर कराकर प्राप्तांकों की सूची के साथ संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों के साथ मास्टर ट्रेनर्स द्वारा चर्चा कर मार्गदर्शन दिया जाएगा।

अतिथि विद्वान मामले में याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई 5 हजार रुपए की कॉस्ट

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर|मप्र हाईकोर्ट ने दमोह के पीजी कॉलेज में अतिथि विद्वान की नियुक्ति के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता पर पाँच हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। डिवीजन बैंच ने कॉस्ट की राशि मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण के कोष में जमा करने का आदेश दिया है। दमोह निवासी वर्षा राजपूत की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह पिछले वर्ष दमोह के पीजी कॉलेज में अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत थी। नए सत्र में अतिथि विद्वान के पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता पर 5 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। पी-4

लोकशिक्षण आयुक्त ने हाईकोर्ट में हाजिर होकर कहा- आदेश का पालन हो गया

अवमानना मामले में दोषी ठहराने के आदेश को रिकॉल करने पर निर्णय सुरक्षित

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत और कटनी डीईओ बीबी दुबे ने बुधवार को हाईकोर्ट में हाजिर होकर कहा कि याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने संबंधी आदेश का पालन कर दिया गया है। उन्होंने एकलपीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के आदेश को रिकॉल किया जाए। सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के आदेश को रिकॉल करने पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

ये है मामला

यह याचिका कटनी निवासी शिखा शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उनके पति स्व. अशोक शर्मा शिक्षा विभाग भोपाल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2014 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। उन्होंने शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने अनुकम्पा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

लोकशिक्षण आयुक्त और कटनी डीईओ को दोषी ठहराया

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने एकलपीठ को बताया कि एकलपीठ के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 15 जनवरी 2021 को एकलपीठ ने लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत और कटनी डीईओ बीबी दुबे को अवमानना का दोषी पाया। एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट में लोकशिक्षण आयुक्त और कटनी डीईओ ने हाजिर होकर आदेश का पालन करने के संबंध में बताते हुए आदेश रिकॉल करने का आग्रह किया। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए। पी-4

वेटरनरी विवि के विद्यार्थी मैप कास्ट की आधुनिक लैब में करेंगे शोध कार्य

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर| जल्द ही वेटरनरी विवि के विद्यार्थी मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट) की आधुनिक लैब में शोध कार्य करते नजर आएँगे। यहाँ के अनुभवियों से ज्ञान लेंगे। इसके लिए विवि और मैप कास्ट के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी तिवारी के अनुसार एमओयू साइन होने के बाद वेटरनरी क्षेत्र में नए अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। विवि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

विवि में शुरू हुए साक्षात्कार- विवि के जबलपुर, रीवा, महू, मुरैना और भोपाल डिप्लोमा कॉलेज के रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। विवि प्रशासन ने बताया कि साक्षात्कार लेने हेतु कमेटी बनाई गई है। यह पहला अवसर है जब उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड तैयार कराया गया है। इसी आधार पर मेरिट तय होगी। उन्हें विवि का हिस्सा बनाया जाएगा। पी-4

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का सिलेबस घटाया

नई दिल्ली| सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस घटा दिया है। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इस विषय में थ्योरी के टॉपिक्स से पांच यूनिट हटाई गई हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर 27 मई को होना है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर संशोधित पाठ्यक्रम चेक कर सकते हैं।

फर्जीवाड़ा करने वाले बीडीएस विद्यार्थियों का स्पेशल एग्जाम कराएगा बीयू

सात साल पहले फर्जीवाड़ा में पकड़े गए थे

कार्यालय प्रतिनिधि, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सात साल पहले बीडीएस परीक्षाओं में फर्जीवाडा करने वाले विद्यार्थियों की स्पेशल परीक्षाएं लेगा। यह निर्णय स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है। अब बीयू की कार्यपरिषद में मुद्दा रखा जाएगा। ईसी स्पेशल परीक्षा की स्वीकृति दे देता है, तो बीयू शासन को पत्र खिलकर परीक्षा कराने की सहमति मांगेगा। बीयू की परीक्षाओं में फर्जीवाडा करने वाले बीडीएस विद्यार्थियों की स्पेशल परीक्षा कराएगा। ये उनका परीक्षा देने का आखिरी मौका हो सकता है। क्योंकि डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डीसीआइ) के नियमों के मुताबिक विद्यार्थियों को नौ साल में डिग्री पूरी करना है। जबकि उनके प्रवेश लेने से अभी तक नौ साल का समय बीत चुका है। बीयू 26 फरवरी से परीक्षाएं ले रहा है, जिसमें उक्त विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। उनकी स्पेशल परीक्षाएं कराएगा। उनकी परीक्षा कराने बीयू कार्यपरिषद की बैठक में स्वीकृति लेगा। विद्यार्थियों का तर्क है कि उन्हें नौ साल में डिग्री करना है, लेकिन उनके तीन साल के लिए रिस्टीकेट होने के कारण बर्बाद किए गए हैं। हालांकि डीसीआई ने परीक्षा कराने का निर्णय बीयू पर छोड दिया है।

क्या है प्रकरण: बीयू के प्रौढ एवं सतत शिक्षा विभाग में बीडीएस की परीक्षाएं कराई जा रही थीं। इसमें परीक्षा हाल में बैठे विद्यार्थियों को जवाहर हास्टल के कमरा नंबर 23 से कापियां लिखकर भेजी जा रही थीं। प्रकरण का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के पूर्व जज अभय कुमार गोहिल ने की थी। प्रकरण में 143 विद्यार्थी शामिल थे। इसमें कई विद्यार्थी तीन साल का रिस्टीकेशन खत्म होने के बाद दोबारा परीक्षा देकर डिग्री लेकर जा चुके हैं। प्रकरण में मानसरोवर डेंटल कॉलेज के सीएमडी कमलकांत तिवारी, प्रिंसिपल विनय कुमार, प्रशासनिक अधिकारी सचिन जैन, अकाउंटेंट बसंत वर्मा, बीयू के गोपनीय शाखा के कर्मचारी हरभान सिंह सेंगर और राधेश्याम शामिल हैं। इस संबंध में बीयू के तत्कालीन अधिकारी संजय प्रकाश तिवारी, डीआर बीके सिंह, यशवंत पटेल, राकेश कुमार चौहान, तत्कालीन निदेशक कालिका यादव और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रो. एसव्हीएस राजपूत से एसटीएफ ने पूछताछ की थी। बीयू एमबीबीएस फाइनल पार्ट 2 और बीडीएस चतुर्थ वर्ष मुख्य और पूरक परीक्षाएं कल से लेना शुरू करेगा। दोनों परीक्षाओं का समय दोपहर दो से शाम पांच बजे तक का रखा गया है।

बीडीएस की परीक्षाओं में फर्जीवाडा करने पर विद्यार्थियों को तीन साल के रिस्टीकेट किया गया था। नौ साल पूरे होने पर उनकी परीक्षाएं कराने के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

डॉ. हरिहर शरण त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू

यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका दिए जाने वाली याचिका SC ने खारिज की

कोर्ट के फैसले से 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर फिरा पानी

एजेंसी • नई दिल्ली

editor@peoplessamachar.co.in

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच 2020 में यूपीएससी की 'प्रारंभिक परीक्षा' में अपना आखिरी मौका गंवा चुके अभ्यर्थियों को एक और अतिरिक्त अवसर देने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले से 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा व न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका यह फैसला केंद्र सरकार को न्यायालय के समक्ष उल्लेख की गई समस्याओं से भविष्य में निपटने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोकता है।

कोर्ट ने कहा, वह संविधान के अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए शीर्ष आदलत को आदेश जारी करने की शक्ति) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि यह एक उदाहरण स्थापित कर देगा और महामारी के दौरान हुई अन्य परीक्षाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने कहा, आयोग ने आंकड़े न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आयोग ने कोरोना के दौरान 2020 में केंद्रीय सेवाओं के लिए कई चयन (अभ्यर्थियों के) किए हैं। यदि यह न्यायालय 2020 की परीक्षा में बैठे कुछ छात्रों के प्रति उदारता दिखाता है, तो यह एक उदाहरण स्थापित कर देगा और इसका अन्य परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा।

निदेशक प्रभात राय तिवारी ने मुक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के माध्यम से स्थापित किए जा रहे विश्व स्तरीय 53 विश्वविद्यालयों का रूपरेखा प्रस्तुत की।

कोरोना संकटकाल में पुस्तकें खरीदने को लेकर डरे हुए हैं अभिभावक

नवीन शिक्षण सत्र की तैयारी, फिर पालकों पर किताबें खरीदने का बोझ

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों से मांगी ई मेल पर किताबों की सूची

भोपाल (आरएनएन)। एक ओर कोरोना का संकट फिर से दहशत फैलाने की आहट दे रहा है वहीं दूसरी ओर नवीन शिक्षण सत्र की तैयारी हो रही है। इस बीच खासकर उन अभिभावकों का दर्द सामने आ रहा है, जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने सभी स्कूलों से ई-मेल पर किताबों की सूची मांगी है।

इनका कहना है कि इन स्कूलों से बड़े विक्रेताओं के अर्मे से बने संबंध अभिभावकों के लिए मुसीबत का कारण बने हैं। इन्हीं के कारण शासन के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। डीईओ कार्यालय ने सीबीएसई स्कूलों के संचालकों से पुस्तकों की सूची मंगाने की तैयारी की है।

बताना होगा कि अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ होने की संभावना है। छोटे विक्रेताओं का आरोप है कि कुछ सीबीएसई स्कूल प्रायवेट पब्लिशर्स की किताबें सिर्फ कमीशन के लिए चलाते हैं। प्रायवेट पब्लिशर्स की किताबों को चलाने में पचास प्रतिशत तक कमीशन मिलता है। यह कमीशन स्कूल प्रबंधन व बुक सेलर के पास जाता है। छोटे सेलरों का कहना है कि प्रायवेट पब्लिशर्स व स्कूल प्रबंधन की सीधे व्यवसायिक रिश्ते होते हैं। प्रायवेट पब्लिशर्स द्वारा स्कूल प्रबंधन को कमीशन देने के बाद उसकी किताबें विशेष दुकान पर बिकने के लिए पहुंचती हैं। विशेष दुकान से भी स्कूल प्रबंधन द्वारा कमीशन लिया जाता है। स्कूल प्रबंधन को दो जगहों से कमीशन मिलता है। कई प्रायवेट पब्लिशर्स पचास प्रतिशत तक कमीशन देते हैं। नतीजतन सीबीएसई स्कूल द्वारा एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाई जाती है। इसका खामियाजा सीधा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। बता दें कि पिछले साल इसी कमीशनखोरी से निपटने के लिए छोटे जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना के समक्ष पूरी समस्या अभिभावकों ने रखी थी।

मांग की गई थी कि सभी स्कूलों की सूची जमा कराई जाए ताकि सभी बुक सेलर सूची के आधार किताबें समय के साथ रख सकें। साथ ही सूची जमा करने बाद बदलने वाले स्कूलों पर एनओसी निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इधर जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि राजपत्र में स्पष्ट प्रकाशन है कि स्कूल संचालक किताबों की सूची स्कूल के बाहर चस्पा करें। इसका पालन सभी को करना होगा। उन्होंने बताया कि हमने भी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वह सूची ई-मेल के माध्यम से कार्यालय में जमा कराएं।

दर्जन भर से ज्यादा प्रकाशक हावी

अभिभावकों का आरोप है कि राजधानी में एक दर्जन से अधिक पब्लिशर्स की किताबें निजी स्कूलों में ज्यादा चलाई जाती है। इसमें ऑक्सफोर्ड, ओरियंट ब्लैक स्वान, सफलवर, पीयरसन, लाग मेन कोरोडोबा, आक्सफोर्ड तरूण, भंजन, रत्ना सागर, विटानिका, कीन्ह इंडिया, एसके, सरस्वती प्रकाशन, ट्रेसियन, नेवरस एजुकेशन, एस चांद, भारती भवन, एवरडीन, होलीकेथ सहित अन्य शामिल हैं। वहीं कुछ सीबीएसई स्कूल प्री कक्षाओं में विभिन्न पब्लिशर्स की किताबों से मटेरियल लेकर खुद की किताब प्रिंट करवाते हैं। यह किताबें भी विशेष दुकानों पर मिलती है। इतना ही नहीं ट्रेसियन पब्लिशर्स में भोपाल डाइस के कई कादर व सिस्टर किताबों के लेखक हैं। यही किताबें मिशनरी स्कूलों में ज्यादा चलती हैं। बुक सेलर बुक्स एन बुक्स, महेश ट्रेडर्स जिंसी, प्रियंका बुक्स छिपी मारवाड़ी रोड, सुरेश स्टेशनरी बैरागढ़, ओह बुक सेंटर सहित अन्य शामिल हैं। अधिकांश छोटे बुक सेलर इन्हीं से बुक्स खरीदकर स्कूलों में सप्लाई करते हैं। इस संबंध में आर्ब डायसिस आफ भोपाल के पीआरओ फादर मारिया स्टीफन ने कहा कि हम इस दिशा में गंभीर हैं। आर्ब डायसिस से जुड़े स्कूलों को विशेष दुकानों से किताब को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्कूलों की किताबें सभी दुकानों पर होना चाहिए। प्रशासन जो विधि तय करे उसके अनुसार सूची जमा करना चाहिए।

लोक सेवा की सेवाएं न देने पर अफसरों को नोटिस

ग्वालियर (नप्र)। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा में संबंधित आवेदक को सेवाएं प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। इस कड़ी में उन्होंने आधा दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। लोकसेवा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लश्कर अनिल बनवारिया, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार ग्रामीण एचवी शर्मा, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मुरार पुष्पा पुषाम, तहसीलदार घाटीगांव अनिल राघव, नायब तहसीलदार मुरार मधुलिका सिंह तोमर व नायब तहसीलदार घाटीगांव विश्राम सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी अधिकारियों से तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

350 प्राध्यापकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी

गुस्सा ● 10 साल से पदोन्नति नहीं होने से है नाराजगी, प्रदेश सहित राजधानी के भी प्रोफेसर हैं शामिल

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। पदोन्नति नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के 350 से अधिक प्रोफेसरों (प्राध्यापक) ने शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। यह आवेदन पिछले एक साल में आए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने वालों में ज्यादातर वह प्रोफेसर हैं, जिनकी सेवा के एक-दो साल बचे हैं। इसमें राजधानी के भी पांच प्रोफेसर शामिल हैं।

प्रोफेसरों का कहना है कि हमें करीब दस साल से पदोन्नति नहीं दी गई। अब एक या दो साल के अंदर शासन पदोन्नति देने वाला भी नहीं है। इस कारण अब घर में रहकर पेंशन लेना ही सही है। उधर, कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी के कारण हर शिक्षक पर कार्य का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सेवानिवृत्ति लेने का एक कारण यह भी सामने आया है।

515 सरकारी कॉलेजों की संख्या प्रदेश में	**471** कॉलेजों में कितने प्रभारी प्राचार्य
394 यूजी कॉलेज प्रदेश के प्राचार्य विहीन	**77** पीजी कॉलेज प्रदेश के प्राचार्य विहीन
7500 कॉलेजों में प्रोफेसरों की संख्या प्रदेश में	**12** ताख (करीब) यूजी व पीजी के विद्यार्थी

कॉलेजों में 2010 के बाद से प्रोफेसरों को पदोन्नति नहीं दी गई है। इसका कारण आरक्षण और एकेडमिक ग्रेड-पे को लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित होना है। इस कारण भी एक-दो साल में सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसरों का मन अब पढ़ाने में नहीं लग रहा है। साथ ही प्रोफेसरों के एरियर्स के भुगतान में भी देरी हो रही है, जबकि यह ग्रांट 31 मार्च के बाद लैप्स हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के बाद दस साल से दे रहीं हैं सेवा: दूसरी तरफ एक प्रोफेसर सेवानिवृत्ति के बाद करीब दस साल से सेवा दे रही हैं। मूल कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद हिंदी की प्रोफेसर डॉ. आभा वाजपेयी करीब आठ साल तक इसी कॉलेज में पढ़ाती रहीं। इसके बाद 2018 से सत्यसाईं कॉलेज में स्वशासी सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। कॉलेज में परीक्षा कराने की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है।

उनका कहना है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद घर में खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगा। डॉ. वाजपेयी इन कार्यों के लिए आने-जाने का ही खर्च लेती हैं।

> लंबे समय से न तो पदोन्नति मिली है और न ही कॅरियर एडवांसमेंट दिया गया। इससे प्रोफेसर कुंठासंत हो गए हैं। इस कारण प्रदेश के करीब 350 से अधिक प्रोफेसरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया है।
>
> – **आनंद शर्मा**, महासचिव, मप्र प्राध्यापक संघ

> यह हर साल की प्रक्रिया है। अगर इस साल सेवानिवृत्ति लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो प्रोफेसरों का अपना निजी कारण रहा होगा।
>
> – **अनुपम राजन**, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

पंचायत सचिव, रोजगार सहायक ने किया लाखों का भ्रष्टाचार

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। आदमपुर छावनी के पंचायत सचिव मर्दन सिंह ठाकुर और रोजगार सहायक प्रीति प्रजापति ने मनरेगा और पंच परमेश्वर योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने विकास कार्य की राशि में से अधिक राशि को निकाल लिया है, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य नहीं कराया है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने मिलकर 15 लाख रुपये का भ्रष्टाचार कर गबन किया है। यह शिकायत बीते दिनों ग्राम पंचायत की सरपंच शकुन नारायण अहिरवार ने की थी।

सरपंच ने बताया कि हरिपुरा और आदमपुर छावनी में सामुदायिक तालाब के लिए एक लाख आठ हजार 82 रुपए स्वीकृत हुए, इसमें से 75 हजार 740 रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन तालाब नहीं बना है। छावनी पठार से आदमपुर तक तालाब बनाए जाने के लिए 2,16115 रुपए स्वीकृत हुए थे, इसमें से 16,340 रुपए निकाले जा चुके हैं लेकिन काम शुरू तक नहीं हुआ।

> सभी विकास कार्य शुरू कर दिए हैं, तालबा से लेकर सोख्ता गड्ढे का काम भी शुरू करा दिया है। सरपंच और उनके बीच बातचीत हो चुकी है। अब कोई बात बाकी नहीं है।
>
> – **मर्दन सिंह ठाकुर**, पंचायत सचिव, आदमपुर

सचिव ने दो से तीन दिन में सभी कार्य शुरू कराने का वादा किया है, वह भी जिला और जनपद पंचायत के अधिकारियों के सामने। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब विकास कार्य की राशि पहले ही निकाल ली गई है और काम नहीं कराया तो अब सचिव क्यों करा रहा है। विभागीय अधिकारी भी इस मामले में जांच करने के बजाय, भ्रष्टाचार पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं।

> – **शकुन नारायण अहिवार**, सरपंच, आदमपुर

सीबीएसई ने सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती की

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कटौती कर देशभर में छात्रों को राहत दी है। इस विषय की परीक्षा 27 मई को निर्धारित है। बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में पांच अध्याय हटा दिए हैं। संशोधित पाठ्यक्रम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण इस सत्र में स्कूल काफी कम दिन चले हैं। अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऐसी स्थिति में छात्र, अभिभावक और शिक्षक पाठ्यक्रम कम किए जाने के पक्ष में हैं। इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम को कम कर पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी थी। इसके बाद सीबीएसई ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में 30 फीसद कटौती की है। इस कारण पाठ्यक्रम के कुछ खास हिस्से बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं होंगे। स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक पाठ्यक्रम में कटौती के बारे में छात्रों को बताएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पाठ्यक्रम में कमी करने के बाबत देशभर के शिक्षाविदों से ठोस सुझाव आमंत्रित किए थे। इस संबंध में 150 शिक्षाविदों ने इस विषय को लेकर अपने सुझाव भेजे थे।

विश्वविद्यालय में बिना मास्क प्रवेश पर पाबंदी

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने तय किया है कि बिना मास्क के किसी को भी परिसर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों के साथ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी से कहा गया है कि वे मुख्य गेट पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएं। परिसर में प्रवेश से पहले मास्क, सैनिटाइजेशन और तापमान अनिवार्य रूप से चेक किया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में हुए संस्थान के दीक्षा समारोह पर भी संकट आ गया था। समारोह के कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय के दो विभाग प्रमुख सहित करीब 10 कर्मचारी संक्रमित हो गए थे। इस समय विभिन्न विभागों में करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हैं।

यूनिवर्सिटी कैंपस में शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे विद्यार्थी। ● नईदुनिया

होलकर, जीएसीसी भी सतर्क : होलकर साइंस कालेज में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। सुरक्षाकर्मियों को कहा गया है कि मास्क के साथ ही तापमान भी चेक किया जाए। इसके बिना किसी को परिसर में न आने दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कामर्स (जीएसीसी) में भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं।

विद्यार्थी और पालक चिंतित : संक्रमण के मामले घटने से आसपास के शहरों से विद्यार्थियों का इंदौर आना शुरू हो गया था। अब फिर से मामले बढ़ने से विद्यार्थी और पालक चिंतित हैं। छात्र संघ नेताओं ने हास्टल खोलने की भी मांग प्रशासन से की थी। इसमें राहत मिल गई थी लेकिन अब फिर से हास्टलों में क्या व्यवस्था रहेगी इसे लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन चिंतित है। एनएसयूआइ के छात्र नेताओं ने बुधवार को विद्यार्थियों की परीक्षा आनलाइन प्रक्रिया से कराने की मांग कुलपति से की।

सुरक्षा के विशेष इंतजाम

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कहा शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम रखना जरूरी है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। दोनों परिसर में मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही हमने विद्यार्थियों तक भी यह संदेश पहुंचाया है कि वे परिसर में आने के पहले मास्क का ध्यान रखें और साथ में सैनिटाइजर की बोतल रखें। संस्थान के जो भी अधिकारी या कर्मचारी बीमार है उन्हें कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा गया है।

आज का इतिहास

1897	अमरनाथ झा – भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री का जन्म हुआ।
2003	हंस राज खन्ना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का निधन हुआ।
2004	वी. नागी रेड्डी, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक का निधन हुआ।
2000	रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन।
2003	गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के 13वें शिखर सम्मेलन में क्वालालंपुर घोषणा स्वीकृत।
2006	दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डेन किलापी पुरस्कार मिला।
2008	एच.डी.एफ.सी. व सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई।

आज का इतिहास

- **1586:** अकबर के दरबारी कवि बीरबल विद्रोही यूसुफजई के साथ एक लड़ाई में मारे गए।
- **1788:** पिट्स रेग्युलेटरी एक्ट पारित किया गया।
- **1836:** सैमुएल कोल्ट ने कोल्ट रिवॉल्वर का पेटेंट लिया।
- **1921:** रूस ने जार्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर कब्जा किया।
- **1925:** पूर्व सोवियत संघ और जापान के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुये।
- **1945:** दूसरे विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- **1948:** हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता डैनी डेन्जोंगपा का जन्म।
- **1952:** नार्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।